आज का विचार
सच्ची दोस्ती बेजुबान होती है, ये तो आंखों से बयान होती है, दोस्ती में दर्द मिलते हैं तो क्या हुआ, दर्द में तो दोस्ती की पहचान होती है।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । रविवार, 8 मार्च, 2026 वर्ष 24, अंक 58, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

जब सरकार, समाज और संस्थाएँ मिलकर एक दिशा व सोच के साथ कार्य करते, तो परिणाम कई गुना बेहतर प्राप्त होते : योगी आदित्यनाथ

सिटी दर्पण संवाददाता
लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जब सरकार, समाज और संस्थाएँ मिलकर एक दिशा व सोच के साथ कार्य करती हैं, तो परिणाम कई गुना बेहतर प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश आज की आवश्यकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास करे तथा निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी करे। प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र द्वारा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है। प्रदेश के जिन जनपदों में और अधिक मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता है, वहाँ नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में राज्य सरकार सहायता कर रही है।

मुख्यमंत्री जी आज जनपद आगरा में यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि 250 बेड युक्त मल्टी सुपर स्पेशियलिटी यथार्थ हॉस्पिटल में व्यापक टर्शियरी केयर सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। मरीजों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए इस अस्पताल में अत्याधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, रोबोटिक सर्जरी, उन्नत क्रिटिकल केयर यूनिट्स और 24x7 इमरजेंसी सेवाएँ उपलब्ध हैं। इससे मरीजों को समय पर और प्रभावी उपचार मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यथार्थ ग्रुप ने अष्ट सिद्धि के रूप में आगरा जनपद में यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की है। जब अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, तभी नौ निधियाँ भी प्राप्त होती हैं। यह हॉस्पिटल इस ध्येय को चरितार्थ करेगा। यथार्थ ग्रुप का यह 8वाँ हॉस्पिटल है। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। सम्प्रभुता सम्पन्न देशों को यह सुविधा अपने नागरिकों को प्रदान करनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में देश को दुनिया में नई पहचान प्राप्त हुई है। हम सभी नये भारत का दर्शन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को देख रहे हैं। देश में विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय के साथ-साथ समग्र विकास की अवधारणा को चरितार्थ किया जा रहा है। देश में अवसंरचनात्मक उन्नति के साथ हाईवे, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो का निर्माण हो रहा है। रेलवे की नई लाइनें बिछायी जा रही हैं। रेलवे के अत्याधुनिक कोच नई तकनीक से लैस हैं। हमें वन्दे भारत, नमो भारत तथा अमृत भारत जैसी उच्च गुणवत्ता युक्त ट्रेनों में यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में एयर कनेक्टिविटी तेजी के साथ समृद्ध होना अद्भुत है। भारत में विगत 70 वर्षों में जितने एयरपोर्ट का निर्माण तथा वायु सेवाओं से सम्बन्धित सुविधाओं में जितनी वृद्धि हुई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्षों में इससे अधिक एयरपोर्ट का निर्माण तथा वायु सेवाओं का संचालन किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले देश में केवल एक एम्स था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने इनकी संख्या बढ़ाकर 06 कर दी। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इनकी संख्या 23 तक पहुँचा दी है। देश में आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, एन0आई0टी0, आई0आई0आई0टी0 आदि संस्थानों की एक लम्बी श्रृंखला स्थापित की गयी है। सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने देश के विकास की तीव्र गति के साथ कदम-ताल मिलाया है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में जनपद गोरखपुर तथा रायबरेली में एम्स का संचालन हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों के साथ-साथ अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ लागू की गयीं। परिणामस्वरूप राज्य के 06 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर सामान्य जीवन-यापन कर रहे हैं। एक समय था कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता था, तो पूरा परिवार परेशान हो जाता था। आज देश में जरूरतमन्दों को 05 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। ह्यआयुष्मान भारत योजनाह्ल की सुविधा के अन्तर्गत केवल उत्तर प्रदेश में 05 करोड़ 60 लाख लोगों को गोल्डेन कार्ड प्रदान किये गये हैं। यह संख्या शीघ्र ही 10 करोड़ पहुँचने वाली है।

मेडिसिनल खेती और माइक्रो-इरिगेशन से बढ़ेगी किसानों की आय: नायब सैनी

नायब सरकार का कम जमीन में ज्यादा कमाई का विजन, जड़ी-बूटी खेती पर फोकस

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

नायब सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने का विजन तैयार किया है। सरकार का फोकस औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती तथा माइक्रो-इरिगेशन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति निर्धारण पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। खरीफ फसलों के मूल्य नीति निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की ₹रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन हरियाणा₹ तथा ₹ रिपोर्ट ऑन वर्किंग ग्रुप ऑन प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन हरियाणा₹ का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि किसानों को मेडिसिनल और एरोमैटिक पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि कम भूमि में अधिक आमदनी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण द्वारा तैयार मेडिसिनल व एरोमैटिक प्लांट्स के प्रमोशन और माइक्रो-इरिगेशन के विस्तार से संबंधित कार्य समूहों की रिपोर्ट का विमोचन करते हुए कहा कि यह क्षेत्र खेती के साथ-साथ प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। मुख्यमंत्री ने अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र को मिलकर इस क्षेत्र की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मेडिसिनल जड़ी-बूटियों के निर्यातकों में शामिल है और इस क्षेत्र में हरियाणा भी अपनी रणनीतिक स्थिति और मजबूत कृषि ढांचे के कारण महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में मेडिसिनल और एरोमैटिक पौधों को टिकाऊ और योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया जाए तो यह क्षेत्र किसानों और उद्यमियों के लिए बड़े आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है।

उन्होंने कहा कि मेडिसिनल और एरोमैटिक पौधों का क्षेत्र केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्शन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का निर्माण और मार्केटिंग जैसी कई गतिविधियां शामिल होती हैं। इस कारण यह क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार , कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक ,हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रविंदर सिंह चौहान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हितेश कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। *-संबंधित पेज 3 पर*

मुर्मू ने संताल युवाओं से शिक्षा अपनाने और भाषा संस्कृति को संरक्षित रखने का आह्वान किया

राष्ट्रपति ने सिलीगुड़ी में आयोजित नौवें अंतरराष्ट्रीय संताल सम्मेलन को संबोधित किया

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में संताल समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन कई महान व्यक्तित्वों को इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा कि अनेक ऐसे वीर रहे जिनके नाम इतिहास में जानबूझकर शामिल नहीं किए गए।

उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित नौवें अंतरराष्ट्रीय संताल सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संताल समुदाय के लिए यह गर्व की बात है कि लगभग 240 वर्ष पहले उनके पूर्वज तिलका मांझी ने शोषण के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। उनके विद्रोह के लगभग 60 वर्ष बाद वीर भाइयों सिदो-कान्हू और चांद-भैरव के साथ बहादुर बहनों फूलो-झानो ने 1855 में संताल हूल का नेतृत्व किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि संताल समुदाय के लोगों ने देश के लिए जितना योगदान दिया है, उसे पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि तिलका मांझी, सिदो-कान्हू और चांद-भैरव जैसे अनेक नाम हैं जो इतिहास में पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाए। यदि उनके योगदान को पूरी तरह शामिल किया जाता तो इतिहास उनके नामों से भरा होता।

उन्होंने संताल समुदाय की वीरता की सराहना करते हुए कहा कि संताल लोग हीनता को स्वीकार नहीं करते और अन्याय के खिलाफ डटकर संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि संताल एक साहसी और स्वाभिमानी समुदाय है, जिसे अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने विकास के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ क्षेत्रों में संताल और अन्य आदिवासी समुदायों तक विकास का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाया है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि आदिवासी समाज को शिक्षा, अवसर और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में कुछ बाधाएं भी सामने आईं। राष्ट्रपति ने कहा कि जब वह यहां आने की तैयारी कर रही थीं, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग इस बैठक के आयोजन के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार ऐसा लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि संताल समुदाय आगे बढ़े, शिक्षा प्राप्त करे और संगठित होकर मजबूत बने।

राष्ट्रपति मुर्मू ने संताल पहचान से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 संताल समुदाय के इतिहास में विशेष रूप से याद किया जाएगा, क्योंकि उसी वर्ष संथाली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संविधान का संथाली भाषा में ओल चिकी लिपि में संस्करण भी जारी किया गया।

इस अवसर पर उन्होंने ओल चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू को भी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया, जिससे संथाली भाषा बोलने वालों को अभिव्यक्ति का नया माध्यम मिला। उन्होंने ह्यबिदु चंदनह्ल, ह्यखेरवाल वीरह्ल, ह्यडालेगे धनह्ल और ह्यसिदो कान्हूझसंताल हूलह्ल जैसे नाटकों के माध्यम से साहित्य और सामाजिक चेतना का भी प्रसार किया।

राष्ट्रपति ने संताल समाज से अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने के साथ अन्य भाषाएं सीखने का भी आान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों ने सदियों से अपने लोकगीत, लोकनृत्य और परंपराओं को संजोकर रखा है तथा प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। यह प्रकृति संरक्षण का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाना चाहिए।

जन औषधि केंद्रों से रोजाना 15 लाख से अधिक लोग खरीदते हैं दवाइयां: नड्डा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की उस महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानें, जिसके माध्यम से देशभर के लोगों तक सस्ती दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। मोदी सरकार की यह पहल कम कीमत वाली जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता को मजबूत बना रही है।

नड्डा ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर कहा कि आज देश के शहरों, कस्बों और गांवों में लगभग 18,000 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, जो लोगों के घरों के नजदीक आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। ये केंद्र परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को संभालने में मदद कर रहे हैं और इलाज के आर्थिक बोझ को कम कर रहे हैं।

वर्तमान में 15 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन इन केंद्रों से दवाइयां खरीदते हैं, जिससे जन औषधि केंद्र लाखों लोगों के लिए एक विश्वसनीय और किफायती स्वास्थ्य समाधान बन गए हैं।

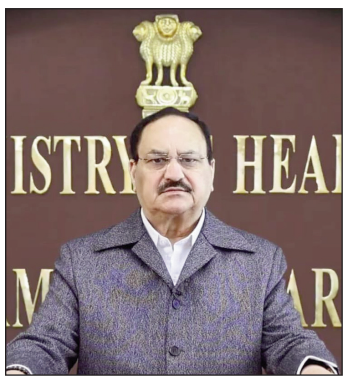

उल्लेखनीय है कि जन औषधि दिवस भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। हर साल 7 मार्च को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य लोगों को जेनेरिक दवाओं के बारे में जानकारी देना और उन्हें सस्ती दवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान, मुफ्त जांच और परामर्श, जन औषधि केंद्रों के बारे में जानकारी- इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि वे कम कीमत में भी अच्छी क्वालिटी की दवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए भारत प्रतिबद्ध: नरेंद्र मोदी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल की जनता और वहां की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने नेपाल में संसदीय चुनाव के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि वह नेपाल के लोगों और सरकार को सफल तथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि यह देखकर हर्ष होता है कि उनके नेपाली भाई-बहन लोकतांत्रिक अधिकारों का इतने उत्साह और जीवंतता के साथ प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा का गर्व का क्षण है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल की जनता और वहां की नई सरकार के साथ मिलकर शांति, प्रगति और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच मित्रता और सहयोग के संबंध भविष्य में और मजबूत होंगे।

केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिया : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

एजेंसी (हि.स.)
हरिद्वार

उत्तराखंड में हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में विशाल जनसमूह को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध है। वोटर लिस्ट का शुद्ध होना लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार राज्य की समस्याओं को चुन-चुन कर हल कर रही है और इसी कारण राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।

अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तराखंड के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा और रामपुर तिराहा कांड जैसी दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों का गठन हुआ, जो आज तेजी से विकास कर रहे हैं।

अमित शाह ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया है और अब इसे संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2026 तक का समय उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते चार वर्षों में राज्य की कई समस्याओं का समाधान किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने नई न्याय संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे लगभग 150 साल पुराने कानूनों को बदलने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2028 तक नई न्याय संहिता के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू हो जाएंगे। इसके बाद किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक फैसला आने में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय व्यवस्था बताया।

अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई दी। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री मोदी का है। इन लोगों ने अपना धर्म और सम्मान बचाने के लिए भारत में शरण ली है और सरकार उन्हें नागरिकता देने के अपने निर्णय पर अडिग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 समाप्त करने, सीएए कानून बनाने, 550 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनाने, बद्रीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण, महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत कई एतिहासिक कार्य किए हैं।

गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी पद पर नियुक्ति पत्र पाने वाले 1900 युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब राज्य में बिना पर्चा और बिना खर्चा के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लाए गए कठोर नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।

अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में होने वाला कुंभ मेला सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगा। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमावर्ती गांवों को प्रथम गांव का सम्मान दिया गया है, जिससे सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी।

अमित शाह ने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र सरकार से लगभग 54 हजार करोड़ मिले थे, जबकि इसके बाद से राज्य को 1.87 लाख करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है। इसके अलावा ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर, रेल और सड़क परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014 में 1.25 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 2.60 लाख रुपये हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 हटाकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार किया गया है। साथ ही सीएए लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट सहित अधिकारी मौजूद रहे।

नाहन में महिला दिवस पर मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे 190 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ

लगभग 152 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा

- वर्तमान प्रदेश सरकार विकास और व्यवस्था परिवर्तन की सोच के साथ कार्य कर रही: विधायक अजय सोलंकी

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च का दिन नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू नाहन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं और क्षेत्र में लगभग 190 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। विधायक अजय सोलंकी ने नाहन चौगान में प्रशासन के साथ तैयारिओं का जायजा लिया और प्रबंधों की समीक्षा भी की। अजय सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 36 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन तथा लगभग 152 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन विकास कार्यों में लोक निर्माण विभाग, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा विद्युत विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं में सड़क निर्माण एवं उन्नयन के विभिन्न कार्य, नाहन जिला अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर कार्यालय भवन, तथा नाहन और पांवटा साहिब में स्मार्ट ग्रिड तकनीक के माध्यम से 24x7 विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की योजनाएं शामिल हैं। विधायक अजय सोलंकी ने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार विकास और व्यवस्था परिवर्तन की सोच के साथ कार्य कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप नाहन विधानसभा क्षेत्र को भी लगातार बड़े विकास कार्यों की सौगात मिल रही है।

मार्च में ही लू जैसी गर्मी, कल से मौसम बदलेगा

- हिमाचल प्रदेश में मार्च की शुरूआत के साथ ही गर्मी का असर तेज

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मार्च की शुरूआत के साथ ही गर्मी का असर तेज हो गया है। राज्य के कई इलाकों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कुछ मैदानी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में 8 मार्च के लिए हीट वेव यानी लू चलने की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद 9 मार्च से मौसम में बदलाव आने के संकेत भी दिए गए हैं।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। विभाग ने 11 मार्च के लिए अंधड़ और बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दिन कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कई शहरों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 6.1 डिग्री अधिक है। सुंदरनगर में 13.6 डिग्री, भुंतर में 10.8 डिग्री और धर्मशाला में 11.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है।

ऊना में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 12.6 डिग्री और पालमपुर में 14 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कांगड़ा में 16.1 डिग्री, मंडी में 13.7 डिग्री और बिलासपुर में 13.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कल्पा में 5.6 डिग्री, केलांग में 3.8 डिग्री और मनाली में 9.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा कुकुमसेरी में 2.4 डिग्री और ताबो में 1.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अन्य स्थानों की बात करें तो कसौली में न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री, जुब्बरहट्टी में 15.2 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 17 डिग्री और पांवटा साहिब में 17 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक दिन तक कुछ स्थानों पर गर्मी का असर बना रह सकता है। लेकिन 9 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाने लगेंगे और तापमान में कुछ गिरावट भी आ सकती है। विभाग के मुताबिक 9 और 10 मार्च को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है, जबकि 11 से 13 मार्च के बीच कई स्थानों पर बारिश हो सकती है।

सार्वजनिक मंचों से मंडी की जनभावनाओं को गाली दे रहे मुख्यमंत्री : जयराम ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी सराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली मंडल में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026 की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश की सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया और नेरचौक मेडिकल कॉलेज की बदहाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के नाचन और बल्ह दौरे के दौरान की गई घोषणाओं को केवल एक छलावा करार देते हुए अजीब विरोधाभास की स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार करोड़ों की 'हाई-टेक रोबोटिक सर्जरी' का ढोल पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर अस्पताल का रेडियोलॉजी विभाग पूरी तरह बंद पड़ा है। ऐसे में ऑपरेशन कैसे संभव हैं। यहाँ तक कि एक अदद एमआरआई मशीन तक की सुविधा सरकार जनता को उपलब्ध नहीं करा पाई है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन सालों से मुख्यमंत्री हर मंच से नेरचौक में एमआरआई मशीन लगाने की बात रट रहे हैं, लेकिन आज की कड़वी हकीकत यह है कि एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट के छुट्टी पर चले जाने से पूरा विभाग ठप है और कार्डियोलॉजी विभाग बिना कैथ लैब के सफेद हाथी साबित हो रहा है। ऐसे में बिना बुनियादी जांच सुविधाओं और जरूरी स्टाफ के रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम स्थापित करने का औचित्य समझ से परे है, योंकि जब मरीज का प्रारंभिक एक्स-रे और एमआरआई ही नहीं हो पाएगा, तो रोबोटिक सर्जरी किस आधार पर की जाएगी? यह जनता की गाढ़ी कमाई को दिखावे की योजनाओं में बर्बाद करने जैसा है।

युवाओं में बढ़ते नशे के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग सीएम को भेजा ज्ञापन

मंडी। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की बल्ह इकाई ने प्रदेश में युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या के खिलाफ सख्त, ठोस और व्यापक कानून बनाने की मांग उठाई है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जंबाल की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने उपमंडलाधिकारी (ना.) बल्ह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। नरेंद्र जंबाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं के बीच नशीले पदार्थों का बढ़ता उपयोग न केवल उनके भविष्य बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और राज्य के विकास के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे की आपूर्ति रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान के लिए व्यापक नीति और सख्त कानून आवश्यक हैं। समिति की उपाध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि नशे के मूल कारणों को दूर करने, उपचार और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर विशेष मिशन और समन्वय सेल स्थापित किया जाना चाहिए। इस मौके पर पूर्व राज्य अध्यक्ष जोगिंद्र वालिया ने भी सरकार से विधानसभा में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाकर ठोस कानून बनाने की मांग की।

खामेनेई की हत्या के विरोध में कश्मीर में हुए प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंध हटे, जनजीवन सामान्य

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद घाटी के कई हिस्सों में हुए प्रदर्शनों के मद्देनजर पूरे सप्ताह लागू प्रतिबंधों को अधिकारियों द्वारा हटाए जाने के बाद शनिवार को कश्मीर में जनजीवन सामान्य हो गया। अधिकारियों ने कहा कि घाटी के सभी हिस्सों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों ने लोगों के जमावड़े को रोकने के लिए लाल चौक समेत कुछ स्थानों पर लगाए गए बैरिकेड हटा दिए हैं।

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में खामेनेई की हत्या के बाद रविवार को हुए व्यापक प्रदर्शनों के बाद लाल चौक स्थित प्रतिष्ठित घंटाघर को चारों ओर बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह लाल चौक और शहर के अन्य क्षेत्रों में दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान फिर से खुल गए और सार्वजनिक और निजी परिवहन सामान्य रूप से चल रहा था। सोमवार को लागू मोबाइल इंटरनेट और प्रीपेड सिम कार्ड सेवाओं पर प्रतिबंध शुक्रवार शाम को बहाल कर दिए गए। हालांकि शिक्षण संस्थान बंद रहे और 9 मार्च को खुलने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि शहर भर से बैरिकेड और अधिकांश पुलिस एवं अर्धसैनिक सीआरपीएफ कर्मियों को हटा लिया गया है लेकिन स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोमवार को कश्मीर के उन हिस्सों में लोगों की आवाजाही और सभा पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे जहां बड़े पैमाने पर सड़क प्रदर्शन हुए थे। कश्मीर जहां लगभग 15 लाख शिया आबादी है में खामेनेई की हत्या की खबर फैलते ही लाल चौक, सैदा कदल, बुडगाम, बांदीपोरा, अनंतनाग और पुलवामा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी सीना पीटते हुए अमेरिका विरोधी और इजरायल विरोधी नारे लगा रहे थे। हालांकि प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहे लेकिन कुछ स्थानों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच मामूली झड़पें हुईं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को मामूली बल प्रयोग करना पड़ा।

एनसीवीईटी ड्यूल स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य बना हिमाचल: शिक्षा मंत्री

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को यहां बताया कि वर्तमान राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (एचपीबोस) के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप बोर्ड को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से 'ड्यूल कैटेगरी' मान्यता प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के साथ हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है, जिसे अवॉर्डिंग बॉडी (एबी) और असेसमेंट एजेंसी (एए) दोनों के रूप में मान्यता मिली है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मान्यता के साथ अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन स्वयं कर सकेगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होगी, जिससे छात्रों को देश और विदेश में रोजगार तथा उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच की दूरी को समाप्त करने पर बल दिया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत पहला प्रमुख कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में बागवानी विषय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को ह्यफ्रूट बाउल ऑफ इंडियाह्न के रूप में जाना जाता है और यह पाठ्यक्रम राज्य की कृषि और बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को बागवानी प्रबंधन, पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक और जैविक खेती से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे राज्य के सेब और अन्य फल उत्पादन से जुड़े उद्योग को भी कुशल युवा कार्यबल उपलब्ध होगा तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड मेजर विशाल ने बताया कि कार्यक्रम एनएसक्यूएफ के स्तर 1 से 4 के अनुरूप संचालित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा

छात्रा से छेड़छाड़ करने पर सुनाई 4 साल कठोर कारावास की सजा

कुल्लू। सत्र न्यायाधीश पीओसीएसओ (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी संजय कुमार पुत्र चुन्नी लाल, निवासी ग्राम फागु, डाकघर धारा, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुमार्ने का दंड दिया है। जुमार्ना अदा न करने की स्थिति में न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी को 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय ने उसे 1 वर्ष के साधारण कारावास और 1000 रुपये के जुमार्ने का दंड दिया है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि जुमार्ना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे 4 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुमार्ना अदा करने का आदेश दिया गया।

डमटाल के छन्नी में घर से 12.76 ग्राम चिट्टा बरामद, महिला तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

नूरपुर पुलिस की सीआईए टीम ने डमटाल क्षेत्र के अंतर्गत गांव छन्नी में एक घर पर दबिश देकर 12.76 ग्राम का चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे नियमित अभियान के तहत अमल में लाई गई है। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की गई है। एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि सीआईए नूरपुर की टीम जब डमटाल क्षेत्र में गश्त और संदिग्धों की निगरानी पर थी, तो गांव छन्नी में एक घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान घर के एक कमरे में रखे फूलदान के अंदर से 12.76 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इस मामले में आरोपी महिला बबली (29 वर्ष), पत्नी सुरिंदर उर्फ झांडी, निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में पुलिस थाना डमटाल में आरोपिया के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है तथा यह भी पता लगाया जा रहा है कि उक्त मादक पदार्थ की तस्करी में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

आतंकवाद-विरोधी अभियान और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए डीजीपी ने बैठक की

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात ने शनिवार को अवंतीपोरा जिले में समग्र सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद-विरोधी अभियानों और कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक अवंतीपोरा जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित की गई और इसमें जम्मू-कश्मीर के विशेष महानिदेशक समन्वय पीएचक्यू एस.जे.एम. गिलानी, कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बर्डी, दक्षिण कश्मीर रेंज के डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू, एसएसपी अवंतीपोरा, अतिरिक्त एसपी अवंतीपोरा, सभी एसडीपीओ और एसओजी के डीएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान डीजीपी ने चल रहे आतंकवाद-विरोधी अभियानों पर विशेष ध्यान देते हुए मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जिसमें गतिज और गैर-गतिज दोनों उपाय शामिल थे। उन्होंने जिले में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी जायजा लिया। डीजीपी ने राष्ट्रविरोधी तत्वों, मादक पदार्थों और अपराध के खिलाफ अभियान को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

स्वच्छता

पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पद्धतियों की जानकारी दी

महिला सप्ताह के तहत कठुआ में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन कठुआ द्वारा चलाए जा रहे महिला सप्ताह अभियान के तहत शनिवार को जिलेभर में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया गया। इस दौरान महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए जागरूकता व स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में महिलाओं की हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, ब्लड शुगर और एनीमिया की जांच की गई। साथ ही मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दी गई। लाभार्थियों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां भी वितरित की गईं। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और बचाव संबंधी उपायों पर परामर्श दिया गया। पोषण अभियान के तहत लगाए गए सूचना स्टॉलों में संतुलित आहार और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी दी गई जबकि आयुष स्टॉलों पर पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पद्धतियों की जानकारी दी गई। यह गतिविधियां जिले के विभिन्न ब्लॉकों में संबंधित ब्लॉक मेडिकल अधिकारियों की निगरानी में आयोजित की गईं जबकि पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग मुख्य चिकित्सा अधिकारी कठुआ डॉ. विजय रैना ने की। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पोषण संबंधी आदतों में सुधार लाना और उन्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

कठुआ, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन कठुआ द्वारा चलाए जा रहे महिला सप्ताह अभियान के तहत शनिवार को जिलेभर में स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया गया। इस दौरान महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए जागरूकता व स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा शिविरों में महिलाओं की हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, ब्लड शुगर और एनीमिया की जांच की गई। साथ ही मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दी गई। लाभार्थियों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां भी वितरित की गईं। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और बचाव संबंधी उपायों पर परामर्श दिया गया।

संक्षिप्त-समाचार

शिमला में 65 दिनों में 28 आदतन चिट्टा तस्कर नजरबंद

शिमला। जिला शिमला में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन तस्करों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। जिला पुलिस शिमला ने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले 65 दिनों में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 28 आदतन चिट्टा तस्करों के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर लागू कर उन्हें नजरबंद कर जेल भेजा जा चुका है। इसी कड़ी में शनिवार को भी चार आदतन नशा तस्करों को निरुद्ध कर जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार इनमें कुमारसैन क्षेत्र के रहने वाले 55 वर्षीय अनिल कुमार उर्फ मोलू को पुलिस थाना कुमारसैन में निरुद्ध किया है। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें वर्ष 2015 में कुल्लू जिले के आनी थाना क्षेत्र में करीब 7 किलो 800 ग्राम चूरा पोस्त बरामद होने का मामला शामिल है। इसके अलावा वर्ष 2019 में कुमारसैन में लगभग 48 ग्राम अफीम और 67 ग्राम चरस बरामद हुई थी तथा वर्ष 2023 में उसके पास से करीब 194 ग्राम चरस भी बरामद की गई थी। पुलिस ने विकास नगर शिमला निवासी 29 वर्षीय मोहित वर्मा को भी छोटा शिमला थाना क्षेत्र से निरुद्ध किया है, जिसके खिलाफ 2021 में करीब 2.15 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा और 12 ग्राम चरस बरामद होने का मामला दर्ज है, जबकि वर्ष 2024 में उसके पास से करीब 16.34 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इसी तरह ठियोग क्षेत्र के शालीन (चमरोट) निवासी 35 वर्षीय अंकुश कुमार को भी छोटा शिमला पुलिस ने हिरासत में लेकर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत नजरबंद किया है।

हिम बस कार्ड को लेकर महिलाओं का विरोध, घेरा एचआरटीसी दफ्तर उठाए सवाल

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बसों में 50 प्रतिशत रियायती सफर के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। इस मुद्दे को लेकर जनवादी महिला समिति की कार्यकताओं ने शनिवार को शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के प्रबंध निदेशक कार्यालय का घेराव किया और सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि सरकार ने 31 जनवरी तक हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य किया है और इसके बाद बिना कार्ड के महिलाओं से बसों में पूरा किराया लिया जाएगा। जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि सरकार को इस मामले में अन्य राज्यों से सीख लेने की जरूरत है। उनका कहना था कि पंजाब सहित कई राज्यों में महिलाएं केवल आधार कार्ड दिखाकर बसों में रियायती सफर कर सकती हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसके लिए अलग से हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य किया जा रहा है।

कृषि विश्वविद्यालय के पशुचिकित्सा वैज्ञानिक को राष्ट्रीय वेट उत्कृष्टता पुरस्कार

धर्मशाला। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के डॉ. जी.सी. नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्रोफेसर तथा टीचिंग वेटरिनरी क्लीनिकल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष डॉ. आदर्श कुमार को 'पीएलआरसी राष्ट्रीय वेट उत्कृष्टता पुरस्कार-2026' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पीएडब्ल्यूएस लर्निंग एंड रिसर्च काउंसिल, भारत द्वारा पशुचिकित्सा विज्ञान और पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, समर्पण तथा संवेदनशील सेवा के लिए प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक कुमार पांडा ने डॉ. आदर्श कुमार को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह पुरस्कार पशुचिकित्सा शिक्षा और क्लीनिकल प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए उनके अथक समर्पण का प्रमाण है, विशेषकर पशु दंत चिकित्सा के विशिष्ट क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और देश भर के युवा पशु चिकित्सकों, शोधकताओं एवं विद्यार्थियों को पशु स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी।

देहरा में सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत, एचआरटीसी की बस से टकराई बाइक

धर्मशाला। कांगड़ा जीका के देहरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-503 पर शनिवार को एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। निमार्णाधीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के नजदीक एक तेज रफ्तार बाइक की एचआरटीसी की बस से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक पल्सर एनएस-200 बाइक पर देहरा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया।

टाइनी टॉट्स प्लेवे स्कूल, चंबा का परीक्षा केंद्र तत्काल प्रभाव से निलंबित

धर्मशाला। प्रदेश में चल रही 10वीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं के बीच उपायुक्त, चंबा की संस्तुति के आधार पर टाइनी टॉट्स प्लेवे स्कूल, मोहल्ला सुरारा, चंबा को बनाए गए परीक्षा केंद्र का दर्जा आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उक्त विद्यालय में परीक्षा दे रहे सभी विद्यार्थियों को शेष बोर्ड परीक्षाओं के संचालन हेतु राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (बॉयज), चंबा में स्थानांतरित किया जाए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हो सके। बोर्ड अध्यक्ष ने जिला प्रबंधक, चंबा तथा जेओए (आईटी) को निर्देशित किया है कि वे 9 मार्च 2026 से पूर्व संबंधित विद्यालय के विद्यार्थियों तथा परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेख एवं सामग्री को नए परीक्षा केंद्र में स्थानांतरित करने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

अम्बाला छावनी की बदलेगी सूरत: 58 करोड़ रुपये से बिछेगा 89 किमीमीटर लंबा स्ट्रॉम वॉटर पाइप लाइन नेटवर्क

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत अम्बाला छावनी में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। सदर क्षेत्र में पहले ही स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज सिस्टम सफलतापूर्वक डाली जा चुकी है, जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है। अब शेष अम्बाला छावनी में ड्रेनेज पाइपलाइन का जाल बिछाया जाएगा।

दो चरणों में अम्बाला छावनी में स्ट्रॉम वॉटर पाइप लाइन डालने का कार्य पूरा होगा। पहले चरण के तहत लगभग 58 करोड़ रुपए की लागत से 89 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन डालने के कार्य को मंजूरी मिल चुकी है जबकि दूसरे चरण के कार्य को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है।

श्री विज आज अपने अम्बाला स्थित आवास पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अम्बाला छावनी में स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा कर रहे थे।

ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि प्रोजेक्ट के पहले चरण में 58 करोड़ रुपये की लागत से बीसी बाजार, लालकुर्ती, आउटर लार्ज रोड (बिजली बोर्ड दफ्तर से एसडी विद्या स्कूल तक), ट्रिब्यून कालोनी, गोविंद नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सुभाष कालोनी, कस्तूरबा कालोनी के अलावा अन्य कालोनियों में स्ट्रॉम वॉटर पाइप लाइन डाली जाएगी। योजना तैयार है और बहुत जल्द जमीनी स्तर पर कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉम वॉटर पाइप लाइन के डलने से कालोनियों व अन्य स्थानों पर अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। ओपन नालियों को बंद किया जाएगा, जिससे जल निकासी तो बेहतर होगी साथ ही लोगों को गंदगी से भी भारी राहत मिलेगी व उनका जीवन सुखद बनेगा।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के अंतर्गत जगाधरी रोड के दूसरी तरफ महेशनगर से लेकर अंतिम छोर में बसी डिफेंस कालोनी तक सारी कालोनियों में स्ट्रॉम वॉटर पाइप लाइन डलेगी। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर योजना को तैयार कर लिया गया है और सरकार से जल्द इसकी मंजूरी मिलने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह सिरसा में आयोजित किया जाएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे मुख्यातिथि

चंडीगढ़। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा में 8 मार्च को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, उनके अधिकारों और समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान की झलक दिखाई देगी। प्रवक्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान, समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को भी साझा किया जाएगा, ताकि महिलाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक किया जा सके।

संक्षिप्त-समाचार

प्रदेश सरकार का सुरक्षित और शिक्षित समाज का निर्माण का है लक्ष्य: कृष्ण कुमार बेदी

चंडीगढ़। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सुरक्षित और शिक्षित समाज का निर्माण करना है। यह केवल सरकार का सपना ही नहीं बल्कि संकल्प भी है, जिसे साकार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री आज नरवाना के एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में नरवाना विधानसभा क्षेत्र को महिला थाना की सौगात दी गई है। इससे क्षेत्र में महिला सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी और महिलाओं के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नरवाना के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड तक करने की योजना है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का आम बजट हरियाणा के चौतरफा विकास का दर्पण है। इसमें महिला, युवा, किसान, कर्मचारी, व्यापारी और उद्यमियों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह एक कल्याणकारी बजट है जो प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने वाला है। इस अवसर पर मंत्री ने नरवाना की बेटी स्वाति आर्य सुपुत्री दिलबाग शास्त्री को यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 366 हासिल कर क्षेत्र और हरियाणा का नाम रोशन करने पर बधाई दी और कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है।

हत्या का प्रयास मामले के आरोपी को सुनाई कारावास व जुमार्ने की सजा

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने हत्या का प्रयास मामले के आरोपी अमित वासी रायसन जिला करनाल को 7 साल कठोर कारावास व 18 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 27 जुलाई 2023 को पुलिस को झगडे के कारण युवक को चोट लगने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम हस्पताल पहुंची जहां पर नीरज चंचल वासी पीपली जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसे उसके भतीजे इस्माईल के साथ देवीलाल पार्क में लड्कों द्वारा मारपीट करने व चाकू से चोट मारने की खबर मिली थी। उसके भतीजे स्माईल ने उसे बताया कि 26 जुलाई 2023 को शाम के समय ताऊ देवी लाल पार्क में घूमने गया था। पार्क में देव वासी समाना, अमित वासी रायसन जिला करनाल व अन्य लडकों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसपर चाकुओं से हमला करके जान से मारने की कोशिश की। उसे ईलाज के लिए हस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच पुलिस चौंकी सैक्टर-4 कुरुक्षेत्र के उप निरीक्षक गुलजार सिंह द्वारा की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी अमित वासी रायसन जिला करनाल को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था। दिनांक 6 मार्च को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अमित वासी रायसन जिला करनाल को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 307 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुमार्ना तथा जुमार्ना न भरने की सूरत में 1 साल अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 साल कठोर कारावास व 1 हजार रुपये जुमार्ना तथा जुमार्ना न भरने की सूरत में 3 माह अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 324 के तहत 3 साल कठोर कारावास व 2 हजार रुपये जुमार्ना तथा जुमार्ना न भरने की सूरत में 3 माह अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 326 के तहत 4 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुमार्ना तथा जुमार्ना न भरने की सूरत में 6 माह अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा सुनाई ।

तापमान बढ़ने पर गेंहूं की फसल को लेकर कृषि वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी

कुरुक्षेत्र। मौसम परिवर्तन के अनुसार तापमान में वृद्धि हो रही है तो कृषि विशेषज्ञ एवं कृषि वैज्ञानिक इसे सामान्य से अधिक बता रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डा. सीबी सिंह के अनुसार तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि गेहूं की फसल को प्रभावित करती है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार बताया कि उच्च तापमान 35 डिग्री से अधिक) में गेहूँ की फसल को बचाने के लिए हल्की और नियमित सिंचाई सबसे जरूरी है। मार्च में बढ़ते तापमान से बचाव हेतु पोटाशियम नाइट्रेट का छिड़काव करें। हवा तेज होने पर सिंचाई से बचें ताकि फसल न गिरे। डा. सीबी सिंह ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन अनुसार उच्च तापमान में गेहूं की फसल के बचाव के लिए जब दिन का तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाए, तो गेहूं में हल्की सिंचाई करें। उन्होंने कहा कि अगर फव्वारा सिंचाई की सुविधा हो, तो दोपहर में तापमान बढ़ने पर 30 मिनट के लिए फव्वारे से सिंचाई करें, यह तापमान को कम रखने में बहुत प्रभावी है। डा. सीबी सिंह ने कहा कि किसानों को मौसम के संबंध में समय समय पर कृषि अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों से परामर्श करना चाहिए।

असम में सुखोई विमान दुर्घटना में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ को उनके पैतृक गांव ककराना में दी गई अंतिम विदाई

चंडीगढ़। असम के कार्बी आंगलोंग में हुई सुखोई (एसयू-30 एमकेआई) विमान दुर्घटना में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ का शनिवार को उनके पैतृक गांव ककराना में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। अपने श्रद्धांजलि संदेश में उन्होंने कहा कि शहीद अनुज वशिष्ठ की कमी न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश को हमेशा महसूस होगी। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। शहीद के अंतिम संस्कार में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक शकुंतला खटक, उपमंडलाधीश आशीष कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीण उपस्थित रहे।

सरकार गांवों के विकास और ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए हैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध: कृष्ण लाल पंवार

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

- पात्र परिवारों को मिला मकान का हक,पंचायत एवं खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने बांटे अलॉटमेंट लेटर

हरियाणा के विकास, पंचायत एवं खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने आज पानीपत के जिला सचिवालय के सभागार में गांव खुखराना के पुनर्स्थापन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 445 पात्र ग्रामीणों को अलॉटमेंट लेटर वितरित किए।इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि खुखराना के ग्रामीणों ने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है और सरकार ने उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है।

मंत्री ने आश्वासन दिया कि जिन लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिए गए हैं, उनकी रजिस्ट्री भी जल्द करवाई जाएगी ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने घर बना सकें। उन्होंने इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गांवों के विकास और ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मंत्री पंवार ने ग्रामीणों से अपील की कि वो जब अपने मकान बनाएं, वहां साफ-सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सरकार गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और सभी ग्रामीण मिलकर आदर्श गांव बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बजट की भी किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

इस अवसर पर एडीसी डॉ पंकज यादव, डीडीपीओ श्री राजेश शर्मा, डीआरओ श्री कनब लाकड़ा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

मोदी सरकार ने देश के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रखा: कुमारी सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

- भारत की ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक फैसलों का निर्णय वॉशिंगटन में नहीं बल्कि नई दिल्ली में होना चाहिए
- सरकार की विदेश नीति से देश की गरिमा और स्वायत्तता कमजोर होती दिखाई दे रही है

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, सिरसा से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि हाल ही में सामने आई खबरें बेहद चिंताजनक हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से 30 दिनों की अनुमति मिली है। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका कौन होता है भारत को अनुमति देने वाला। उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और उसके आर्थिक तथा विदेश नीति से जुड़े निर्णय देश के राष्ट्रीय हितों के आधार पर होने चाहिए, किसी दूसरे देश की मंजूरी पर नहीं।

कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की विदेश नीति से देश की गरिमा और स्वायत्तता कमजोर होती दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने देश के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। भारत की ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक फैसलों का निर्णय वॉशिंगटन में नहीं बल्कि नई दिल्ली में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्हें ऐसा क्या डर है कि वे हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर अमेरिका की बात मानने को तैयार दिखाई देते हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र और संतुलित रही है, लेकिन वर्तमान सरकार के रवैये से यह धारणा बन रही है कि देश की नीतियों पर बाहरी दबाव हावी हो रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र, संतुलित और पूरी तरह राष्ट्रीय हितों पर आधारित होनी चाहिए। देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव से ऊपर होने चाहिए।

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक बार फिर आम जनता की जेब पर सीधा प्रहार किया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ाकर और कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपये की वृद्धि कर मध्यम वर्ग तथा आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में लगभग 307 रुपये की बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पहले ही बढ़ती कीमतों, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली-पानी के बिल और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की महंगाई से जूझ रहे परिवार अब रसोई गैस के इस नए झटके से और अधिक परेशान होंगे। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियाँ लगातार आम नागरिक की रसोई और रोजगार दोनों पर भारी पड़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लिया जाए और आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

पितृ जन की मुक्ति दिलाने और अक्षय फल प्राप्ति के लिए अहम होगी अष्टकोशी पैदल परिक्रमा: धुमन सिंह

सिटी दर्पण संवाददाता

कुरुक्षेत्र

- चैत्र कृष्ण चौदस 18 मार्च को होगी अष्टकोशी यात्रा, सुबह 5 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक पूरी की जाएगी यात्रा
- हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह ने किया कार्यक्रम स्थल का अवलोकन

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र की प्राचीन और ऐतिहासिक परम्पराओं को जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों में अष्टद्वोशी यात्रा भी शामिल है। यह अष्टकोशी यात्रा पितृ जनों की मुक्ति दिलाने और अक्षय फल प्राप्तगामी होती है। यह अष्टकोशी यात्रा चैत्र कृष्ण चौदस 18 मार्च को सुबह 5 बजे शुरू होगी और सायं 6 बजे यात्रा का समापन होगा।

सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच शनिवार को अष्टकोशी यात्रा को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की परिक्रमा वास्तव में सन्निहित सरोवर की परिक्रमा है इस तीर्थ का विस्तार चारों दिशाओं में दो दो कोस था तीर्थ के तट पर स्थापित मंदिरों में दान व स्नान की परम्परा सदियों से चली आ रही है कुरुक्षेत्र की अष्टकोशी परिक्रमा भी पितृजन की मुक्ति दिलाने वाली व अक्षय फल प्राप्त गामी होती है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र अष्टकोशी परिक्रमा हजारों साल पुरानी है सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों ने उपवास रख जन नियंता भगवान ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए अष्टकोशी की परिक्रमा की और अपने-अपने देवत्व भार को ग्रहण कर सृष्टि संयोजन का कार्य प्रारंभ किया त्रिदेवों के पश्चात सैकड़ो सालों से सदैव प्रतिवर्ष देवता और धार्मिक पुरुषों ने अष्टकोशी भूमि की यात्रा अनवरत रूप से जारी रखी एक बार यात्रा करने पर मनुष्य की समस्त मनोकामना को पूरा करने वाली दो बार अष्टकोसी यात्रा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है तीन बार अष्टकोसी यात्रा करने पर अक्षय लोको की प्राप्ति होती है । उन्होंने कहा कि आदिकाल से चली आ रही यह परिक्रमा साहसिक तीर्थ यात्रा है खेतों की छोटी-छोटी पगडंडी पर सरस्वती नदी के किनारे किनारे चलते हुए लगभग 24 किलोमीटर की यह यात्रा सूर्योदय से नाभकमल मंदिर से चलकर नाभ कमल मंदिर में सूर्य अस्त तक पूर्ण होती है कुरुक्षेत्र मोक्षदायक धार्मिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ है। यह केवल महाभारत युद्ध भूमि ही नहीं भगवान कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई गीता जन्मस्थली भी है।

अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उप राज्यपाल बनाए जाने पर अप्रवासी भारतीयों में भी खुशी की लहर

सिटी दर्पण संवाददाता

कुरुक्षेत्र

अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उप राज्यपाल बनाए जाने पर अमेरिका के अप्रवासी भारतीयों में भी खुशी की लहर है। कुरुक्षेत्र की धरती से अमरीका के विभिन्न राज्यों में वर्षों से व्यवसाय का संचालन कर रहे जेएमडी ग्रुप ऑफ कम्पनीज के प्रमुख नरेंद्र जोशी एवं जसबीर सैनी बॉस्टन जोकि आजकल भारत प्रवास पर हैं उन्होंने तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उप राज्यपाल बनाए जाने शुभकामनाएं दी हैं। जोशी तथा सैनी ने कहा कि वे शीघ्र ही तरनजीत सिंह संधू को व्यक्तिगत तौर पर मिलकर शुभकामनाएं देंगे। उन्होंने बताया कि वे अमरीका में भी तरनजीत सिंह संधू के भारतीय राजदूत रहते हुए अनेक कार्यक्रमों में उनसे मिल चुके हैं। तरनजीत सिंह संधू बहुत ही मिलनसार एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जोशी ने कहा कि तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के सबसे अनुभवी राजनयिकों में से एक रहे हैं, जिन्होंने वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में कई बार अपनी सेवाएं दी हैं। 1997-2000 के दौरान, वे भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव (राजनीतिक) थे, जहां वे अमेरिकी कांग्रेस के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे। फिर, 2013-2017 के दौरान, उन्हें भारतीय दूतावास में उप मिशन प्रमुख बनाया गया। उन्होंने फरवरी 2020 में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला और 1 फरवरी, 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति तक उस पद पर बने रहे। सेवानिवृत्ति के बाद, वे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा में शामिल हो गए। वाशिंगटन में अपनी नियुक्ति से पहले, वे 2017 से 2020 तक श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त थे।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा में लगेंगे महिला स्वैच्छिक रक्तदान शिविर: डॉ. मुक्ता कुमार

सिटी दर्पण संवादादता

चंडीगढ़

- सभी जिलों में आयोजित होंगे शिविर, महिलाओं को रक्तदान व स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किया जाएगा प्रेरित

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को समर्पित एक विशेष पहल के तहत 8 मार्च को हरियाणा के सभी जिलों में महिला स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन हरियाणा राज्य रक्त संचरण परिषद तथा स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की देखरेख में राज्य के सभी लाइसेंस प्राप्त रक्त केन्द्रों, जिला नागरिक अस्पतालों और निजी रक्त केन्द्रों किया जाएगा।

हरियाणा राज्य रक्त संचरण परिषद की परियोजना निदेशक डॉ. मुक्ता कुमार ने बताया कि इन रक्तदान शिविरों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रक्तदान को महादान माना जाता है और एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन देने में सहायक होती है। महिला दिवस के अवसर पर आयोजित यह अभियान समाज सेवा और मानवता की भावना को मजबूत करने का संदेश देगा।

उन्होंने कहा कि यह राज्य स्तर पर अपनी प्रकार की पहली अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को समाज सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी है। यह अभियान ह्लस्वस्थ नारी झ्र स्वस्थ परिवारह्व के संकल्प को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इन रक्तदान शिविरों में उनके स्वास्थ की भी जांच की जाएगी। महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच तथा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किये जाएंगे।रक्तदानी महिला में हीमोग्लोबिन स्तर 12.5 या इससे अधिक होना चाहिए। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे स्वैच्छा रक्तदान में भागीदारी कर रक्तदान करें और जीवन रक्षक अभियान को सफल बनाए।

गांव डीग के ग्रामीणों को मिली खेल प्रांगण और सामुदायिक केंद्र की सौगात: विश्राम कुमार मीणा

सिटी दर्पण संवाददाता

शाहाबाद

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत 2 से 3 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा देगी तो युवाओं के लिए खेल प्रांगण की सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव में सामुदायिक केन्द्र के लिए घोषित की गई अनुदान राशि जल्द ही ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवा दी जाएगी और जल्द ही सामुदायिक केन्द्र का निर्माण शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं रात्रि प्रवास में ग्रामीणों की मांग को पूरा करते कहा कि सोमवार से प्राइमरी स्कूल डीग में एक ओर टीचर की डयूटी लगाई जाएगी, इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अभी तक डीग गांव के प्राइमरी स्कूल में 66 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही टीचर था। ग्रामीण की इस समस्या को पूरा करते हुए उपायुक्त ने शिक्षा विभाग को सोमवार से एक ओर टीचर को गांव भेजने के निर्देश दिए।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा गांव डीग के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं और शिकायतों को सुन रहे थे। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में करीब 50 शिकायतें पहुंची, इनमें से 20 शिकायतें पेंशन और परिवार पहचान पत्र तथा 15 शिकायतें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना से सम्बन्धित थी। इनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गया। इससे पहले गांव डीग में पहुंचने पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा का सरपंच नेहा देवी ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उपायुक्त ने विभिन्न विभाग के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान बिजली तारें बदलवाने, बिल ठीक करवाने, पीएम आवास योजना का लाभ लेने, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां ठीक करवाने, पेंशन लगवाने, गली व रास्तों का निर्माण करवाने के संबंध में ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने खेल ग्राउंड की मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि पंचायत की

जमीन पर युवाओं के खेलने, ग्रामीणों के सैर करने की व्यवस्था की जाएगी। इस खेल मैदान को पंचायत के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही गांव के सामुदायिक केंद्र के निर्माण को पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मंजूर की गई 5 लाख की ग्रांट से पूरा करवाया जाएगा।

इस मौके पर एसडीएम अनिल कुमार दून, जिला परिषद के सीईओ शंभू राठी, डीएसपी रामकुमार, सरपंच नेहा देवी, एक्सईएन मुनीष बब्बर, एसडीओ पंचायती राज ईशान कपूर, एसएचओ जगदीश टामक, सरपंच प्रतिनिधि सुमित कुमार, एसडीओ पब्लिक हेल्थ विनोद कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

रात्रि ठहराव कार्यक्रम में बैंक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, क्रीड, खाद्य आपूर्ति विभाग, यूएचबीवीएन, एसडीएम कार्यालय, वन विभाग ने शिविर लगाकर ग्रामीणों को अपने-अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही योजनाओं का लाभ लेने के लिए मौके पर ही ग्रामीणों के आवेदन भी करवाएं गए।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सरपंच नेहा देवी को कहा कि सरकार ने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया हुआ है। इसकी शुरूआत लाडवा विधानसभा से ही की गई है। इस अभियान के तहत 14 वर्ष से ऊपर और 15 वर्ष पूरे होने से पहले युवतियों को एचपीवी का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार में इस टीके की कीमत कई हजार रुपए है और सरकार इस टीका का अभियान चलाकर फ्री में लगा रही है। अन्य देशों ने पहले ही इसको शुरू किया हुआ है। ऐसे में सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरपंच गांव में एक शिविर का आयोजन कर पात्रों को टीकाकरण करवाएं।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सरकार द्वारा सोलर सिस्टम लगवाने पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी मुहैया करवा रही है। दो किलोवाट तक का सोलर के लिए कोई भी पैसा देने की जरुरत नहीं पड़ती है। जो प्रदेश सरकार की योजना में शामिल नहीं हैं, उन्हें तीन किलोवाट पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। गांव डीग से 10 आवेदन हुए हैं, इनमें से 4 घरों पर सोलर सैट लग चुके हैं, जबकि 6 आवेदनों की फाइल प्रोसेस में है।

पीएम आवास का लाभ प्राप्त करने के लिए सतीश, सुनीता, जोगिंद्रो, संदीप कुमार, सलोचना, महक रानी और दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मंजू, अनुराधा, राज रानी ने लिखित में समस्याएं बताई। इसके अलावा गली का निर्माण के लिए अनिल कुमार, सूरज, अजय कुमार, ओवरफ्लो तालाब की समस्या के समाधान के लिए सुरेंद्र कुमार, भूमि की तकसीम करवाने के लिए रामपाल और नाले की सफाई के लिए विपिन, प्रदीप ने समस्या जाहिर की।

संपादकीय

ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित, एल पी जी कीमतों में बदलाव के पीछे आर्थिक संतुलन की कहानी

घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है, जबकि सरकार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि देश के पास ऊर्जा भंडार की स्थिति 'सुविधाजनक' या संतोषजनक बनी हुई है। ऐसे में आम उपभोक्ताओं के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति स्थिर बताई जा रही है, तब रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों और सरकारी सूत्रों के अनुसार इसके पीछे कई आर्थिक और नीतिगत कारण काम कर रहे हैं, जिनका सीधा संबंध वैश्विक बाजार, सब्सिडी नीति और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति से है। सबसे पहले वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति को समझना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहा है। भले ही भारत के रणनीतिक और व्यावसायिक भंडार पर्याप्त स्तर पर हों, लेकिन घरेलू एलपीजी की कीमतें सीधे तौर पर वैश्विक एलपीजी बेंचमार्क से प्रभावित होती हैं। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में थोड़ी भी वृद्धि होने पर उसका असर घरेलू कीमतों पर दिखाई देता है। ऊर्जा क्षेत्र के सूत्र बताते हैं कि हाल के महीनों में मध्य पूर्व और यूरोप से जुड़े भू-राजनीतिक तनावों ने ऊर्जा आपूर्ति की लागत को बढ़ाया है। वैश्विक शिपिंग दरों में बढ़ोतरी, बीमा लागत और आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितता ने एलपीजी के आयात को महंगा बना दिया है। इसका दबाव अंततः घरेलू बाजार पर पड़ता है, क्योंकि तेल विपणन कंपनियों को आयात लागत और खुदरा कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति है। पिछले वर्षों में सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई बार एलपीजी की कीमतों को नियंत्रित रखा, जबकि अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हुई थीं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को भारी अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ा। यानी उन्हें लागत से कम कीमत पर सिलेंडर बेचना पड़ा। इस घाटे की भरपाई के लिए समय-समय पर कीमतों में संशोधन करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया मूल्य वृद्धि उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तीसरा पहलू सब्सिडी नीति से जुड़ा है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में एलपीजी सब्सिडी को अधिक लक्षित बनाने की नीति अपनाई है। पहले बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इसे मुख्य रूप से गरीब और पात्र लाभार्थियों तक सीमित किया गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को विशेष सहायता दी जाती है, लेकिन सामान्य उपभोक्ताओं को बाजार आधारित कीमतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कीमतों में थोड़ी भी वृद्धि सीधे उपभोक्ताओं को महसूस होती है। ऊर्जा अर्थशास्त्रियों के अनुसार 'सुविधाजनक ऊर्जा भंडार' का अर्थ यह नहीं होता कि कीमतें स्थिर रहेंगी। ऊर्जा भंडार मुख्य रूप से आपूर्ति सुरक्षा से जुड़े होते हैं। यानी यदि वैश्विक बाजार में अचानक संकट पैदा हो जाए तो देश के पास कुछ समय तक ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहे। लेकिन खुदरा कीमतें मुख्य रूप से आयात लागत, कर संरचना और वितरण लागत से तय होती हैं। भारत की ऊर्जा संरचना भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश तेजी से स्वच्छ ऊर्जा और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एलपीजी को कोयले और पारंपरिक ईंधन की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को एलपीजी से जोड़ा गया है। इससे एलपीजी की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती मांग के कारण आयात पर निर्भरता भी बढ़ती है, जो कीमतों को प्रभावित करती है। इसके अलावा कर संरचना भी कीमतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एलपीजी की अंतिम खुदरा कीमत में केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न कर, परिवहन लागत और डीलर मार्जिन शामिल होते हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी पर कर अपेक्षाकृत कम होते हैं, लेकिन परिवहन और वितरण से जुड़ी लागतों का प्रभाव कीमतों पर पड़ता है। सरकार के सामने एक संतुलन बनाने की चुनौती भी रहती है। एक ओर उसे उपभोक्ताओं को राहत देने की जिम्मेदारी निभानी होती है, तो दूसरी ओर तेल कंपनियों की वित्तीय सेहत को भी बनाए रखना होता है। यदि कीमतों को लंबे समय तक कृत्रिम रूप से कम रखा जाए तो कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ सकता है, जिसका असर पूरे ऊर्जा क्षेत्र पर दिखाई दे सकता है। ऊर्जा नीति विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में एलपीजी की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए भारत को घरेलू उत्पादन बढ़ाने, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने और गैस आपूर्ति के दीर्घकालिक अनुबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा। साथ ही, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की नीति भी महत्वपूर्ण होगी। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हालिया वृद्धि केवल घरेलू नीति का परिणाम नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, आयात लागत, सब्सिडी नीति और तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति जैसे कई कारकों का संयुक्त प्रभाव है। भले ही देश के पास ऊर्जा भंडार संतोषजनक स्तर पर हों, लेकिन वैश्विक बाजार से जुड़ी वास्तविकताएं घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचने से नहीं रुकतीं। यही कारण है कि 'सुविधाजनक ऊर्जा भंडार' के बावजूद एलपीजी की कीमतों में समय-समय पर बदलाव देखने को मिलता है।

आयुर्वेद परंपरा और नवाचार को नई गति दे रही 'नारी शक्ति'

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस वर्ष की वैश्विक थीम 'राइट्स, जस्टिस, एक्शन-फॉर ऑल वूमेन एंड गर्ल्स', महिलाओं और बालिकाओं के अधिकार, समानता और उनके समग्र सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने का आह्वान करती है। यह थीम इस बात पर बल देती है कि हर महिला और बालिका को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए।

डॉ. रितेश

भारतीय समाज में महिलाओं को परिवार की 'पहली डॉक्टर' माना जाता है। घर की रसोई में उपलब्ध जड़ी-बूटियों से परिवार सदस्यों की मौसम के अनुसार सेहत का ख्याल रखना आयुर्वेदिक जीवन शैली का अंग है। ग्रामीण भारत में आज भी दादी-नानी के घरेलू नुस्खे आयुर्वेदिक ज्ञान की जीवंत मिसाल हैं। सर्दी-जुकाम में तुलसी और अदरक का काढ़ा, पेट दर्द में अजवाइन का उपयोग या त्वचा की देखभाल के लिए हल्दी और चंदन का प्रयोग ये सभी आयुर्वेदिक परंपरा के ही रूप हैं, जिन्हें महिलाओं ने पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा में आयुर्वेद ने सदैव महिला स्वास्थ्य को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आयुर्वेद में महिला को केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के स्वस्थ भविष्य की आधारशिला माना गया है।

गर्भावस्था तथा प्रसव देखभाल से लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अनेक विषयों पर आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार महिला का स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ा होता है। संतुलित आहार, योग, ध्यान और प्राकृतिक औषधियां महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं। विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान आयुर्वेदिक देखभाल को बहुत महत्व दिया गया है। आयुर्वेद में 'गर्भसंस्कार' की परंपरा भी इसी का हिस्सा है, जिसमें गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। आज की महिला आयुर्वेदाचार्य इन परंपरागत ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा समझ के साथ जोड़कर महिलाओं के लिए समग्र स्वास्थ्य समाधान विकसित कर रही हैं। भारतीय ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि समाज में महिलाओं की भूमिका केवल रोगी के रूप में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की संरक्षक के रूप में भी रही है।

आज आयुर्वेद केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व के अनेक देशों में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इस वैश्विक विस्तार में भी महिला विशेषज्ञों की भूमिका उल्लेखनीय है। कई महिला आयुर्वेदाचार्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, शोध परियोजनाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेकर आयुर्वेद के सिद्धांतों और उपचार पद्धतियों को दुनिया तक पहुंचा रही हैं। इससे भारत की इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो रही है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, पंचकूला सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष कार्यक्रमों में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है, जोकि समाज में महिलाओं को प्राकृतिक जीवनशैली एवं आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या आदि को अपनाकर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करते हैं। इस वर्ष की थीम 'राइट्स-जस्टिस-एक्शन' के संदर्भ में आयुर्वेद हमें यह संदेश देता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य का अधिकार केवल उपचार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि निवारक स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक संतुलन और जीवनशैली के समुचित मार्गदर्शन तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

महिला दिवस के अवसर पर यह स्वीकार करना आवश्यक है कि आयुर्वेद की शक्ति ग्रंथों के साथ, उन महिलाओं के समर्पण और ज्ञान में भी निहित है, जो इस परंपरा को संजोते हुए उसे भविष्य की ओर अग्रसर कर रही हैं। परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा से लेकर आधुनिक चिकित्सा और शोध तक, महिलाएं आयुर्वेद की सशक्त वाहक हैं। महिला दिवस 2026 की थीम आयुर्वेद के उस मूल सिद्धांत से भी मेल खाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इस प्रकार 'नारी शक्ति' न केवल आयुर्वेद की संरक्षक है, बल्कि उसके नवाचार और वैश्विक विस्तार की प्रेरक शक्ति भी है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर हम यह संकल्प लेते हैं कि महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य अधिकार, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे तथा आयुर्वेद के सिद्धांतों के माध्यम से स्वस्थ, सशक्त और जागरूक समाज के निर्माण में योगदान देंगे। 'स्वस्थ नारी-सशक्त समाज' की भावना के साथ सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आज का राशिफल

मेष: कुछ प्रतिकूल गोचर का क्षोभ दिन-भर रहेगा। सुबह-सुबह की महत्वपूर्ण सिद्धि के बाद दिन-भर उत्साह बना रहेगा। किसी लाभदायक कार्य के लिए व्ययकारक स्थितियां पैदा होंगी। ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा। मनोरथ सिद्धि का योग है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: अवरुद्ध कार्य संपन्न हो जाएंगे। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा रहेगी। प्रसन्नता के साथ सभी जरूरी कार्य बनते नजर आएंगे। कुछ कार्य भी सिद्ध होंगे। व्यर्थ की भाग-दौड़ से यदि बचा ही जाए तो अच्छा है। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढने के अवसर लाभकारी सिद्ध होंगे। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते है। सभा-गोष्ठियों में मान-सम्मान बढ़ेगा। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनाने के लिए भाग-दौड़ रहेगी। भाई-बहनों का प्रेम बढ़ेगा। धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी। सुखदायी समय है। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी। बुद्धितत्व की सक्रियता से अल्प लाभ का हर्ष होगा। सुखद समय की अनुभूतियां प्रबल होगी। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: रुका हुआ लाभ आज प्राप्त हो सकता है। मनोविनोद बढ़ेगे। व्ययाधिक्य का अवसर आ सकता है। कामकाज की अधिकता रहेगी। लाभ भी होगा और पुराने मित्रों से समागम भी होगा। व्यवसायिक अभ्युदय भी होगा और प्रसन्नताएं भी बढ़ेगी। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। शुभ कार्यों का लाभदायक परिणाम होगा। श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां होगी। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। शुभ कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी और शुभ समाचार भी मिलेंगे। *(सिटी दर्पण)*

तुला: पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। रुका हुआ लाभ आज प्राप्त हो सकता है। जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। शुभ कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी और शुभ समाचार भी मिलेंगे। लाभकारी गतिविधियों में सक्रियता रहेगी। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: अपने हितैषी समझे जाने वाले ही पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ एकाग्रता की प्रवृत्ति बनेगी। कामकाज की व्यस्तता से सुख-आराम प्रभावित होगा। धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी। *(सिटी दर्पण)*

धनु: हित के काम में आ रही बाधा मध्याह्न पश्चात दूर हो जाएगी। जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा। परिवारजन का सहयोग काम को बनाना आसान करेगा। अपने काम आसानी से बनते चले जाएंगे। थोड़े प्रयास से कार्य सिद्ध होंगे। *(सिटी दर्पण)*

मकर: परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। आर्थिक लाभ हेतु किये गए कार्यों का तत्काल प्रतिफल मिलेगा। बौद्धिक उलझनें बनी रहेंगी। लाभमार्ग प्रशस्त होगा। नवीन उद्योगों के अवसर बढ़ेगे व अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: विद्यार्थियों को लाभ। मेहमानों का आगमन होगा। राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। ड्रूषचतनीय वातावरण से मुक्ति मिलेगी। नैतिक दायरे में रहें। मेहमानों का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। पारिवारिक विवाद टालें। *(सिटी दर्पण)*

मीन: शत्रुपक्ष पर आप हावी रहेंगे। पारिवारिक परेशानी बढ़ेगी। कुछ प्रतिकूल गोचर का क्षोभ दिन-भर रहेगा। यश-प्रतिष्ठा में वृद्धि व शिक्षा में परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञानार्जन का वातावरण बनेगा। *(सिटी दर्पण)*

'केयर इकॉनमी': विकसित भारत @2047 की आधारशिला

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए, हम न सिर्फ भारत की महिलाओं की उपलब्धियों, बल्कि उनकी दृढ़ता, पालन-पोषणकारी, दृढ़ निश्चयी और परिवर्तनकारी अदम्य भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। महिला दिवस महज कैलेंडर की एक तारीख भर नहीं है, बल्कि यह इस बात की पुष्टि है कि भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका परिधि में नहीं, बल्कि केंद्र में रही है। हमारी महिलाएँ केवल संस्थानों और बोर्डरूम तक सीमित नहीं हैं; वे आंगनों, खेतों, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक तंत्र में नेतृत्व का एक नया अध्याय रच रही हैं।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्रों में वे नई पहचान गढ़ रही हैं। रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारी विशिष्ट सेवाएँ दे रही हैं-लड़ाकू विमान उड़ाने से लेकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने तक, वे नए क्षितिज का विस्तार कर रही हैं।

समूचे ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करोड़ों महिलाएँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही हैं। वे आर्थिक स्वतन्त्रता की नींव पर सामूहिक समृद्धि का सृजन कर रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक स्तर पर नए मानक स्थापित कर रहा है। यह साबित करता है कि जमीनी स्तर का नेतृत्व समावेशी और प्रभावशाली, दोनों ही है। वैश्विक खेल मंच पर, उत्कृष्टता और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिलाएँ लगातार देश को गौरवान्वित कर रही हैं।

इतिहास साक्षी है कि भारतीय नारी का सामर्थ्य कोई नई बात नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने निडर होकर अपने देश की रक्षा की। सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देकर बेटियों की शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई। देवी अहिल्याबाई होलकर ने बुद्धिमत्ता एवं करुणा से जन कल्याण को शासन के केन्द्र में रखा। नीतिगत सुधार और दृढ़ संकल्प की उनकी विरासत आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है।

आज, यह अमिट विरासत सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों में परिलक्षित होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि विकास की अग्रदूत के रूप में मान्यता दी गई है। 'महिला-नेतृत्व वाला विकास' आज एक सशक्त नीतिगत-दृष्टि है, जो बजट, कार्यक्रमों और संस्थागत सुधारों में परिलक्षित होती है। महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि उत्सव को बदलाव के रूप में साकार करना होगा। प्रत्येक महिला-चाहे वह किसी निगम का नेतृत्व करती हो, वर्दी में सेवा करती हो, खेत में पसीना बहाती हो, छोटा उद्यम चलाती हो या घर पर अपने परिवार का भरण-पोषण करती हो, मोदी सरकार उसका अभिनंदन करती है।

हमारी प्राचीन सभ्यतागत परंपरा में नारी शक्ति का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। वह परंपरा की धरोहर को सहेजती है और बदलाव की बयार को नेतृत्व देती है। उसके व्यक्तित्व में करुणा का सागर भी है और साहस का अडिग शिखर भी; वह जहाँ एक ओर नैतिक मूल्यों की मयार्दा में बंधी है, वहीं दूसरी ओर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए उतनी ही महत्त्वाकांक्षी भी है। बहुआयामी भूमिकाओं को एक साथ साधने का उसका कौशल सदियों से भारतीय नारी की जीवन-शैली का अभिन्न हिस्सा रहा है। वह अपनी जिम्मेदारियों को सहज भाव से ओढ़ती है, धैर्य के साथ परिवार की नींव को सींचती है और अपने 'शांत नेतृत्व' से समाज को एक नई दिशा और शक्ति प्रदान करती है।

समाज की हर दृश्यमान उपलब्धि के पीछे एक आधारशक्ति अनवरत कार्य करती है-'देखभाल की अर्थव्यवस्था' (Care Economy)। यह वह मौन ऊर्जा है जो भारत के अस्तित्व को हर पल संबल प्रदान करती है। यह उस माँ का समर्पण है, जो सूर्योदय से पूर्व अपनों के लिए चूल्हा सुलगाती है और फिर जीविका की चुनौतियों की ओर निकल पड़ती है। यह उस पत्नी की अटूट निष्ठा है, जो कठिन से कठिन समय में भी परिवार की नींव को दरकने नहीं देती। यह उस बेटी का निःस्वार्थ भाव है, जो दिनभर की थकान के बाद भी रात के पहर अपने वृद्ध माता-पिता के सिरहाने बैठती है। यह शक्ति किसी यश या प्रशंसा की आकांक्षी नहीं है; वह तो बस कर्तव्य की उस अविरल धारा की तरह है, जो बिना शोर मचाए सृजन करती रहती है।

अन्नपूर्णा देवी

ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं के योगदान का एक विशाल हिस्सा-विशेषकर अवैतनिक देखभाल (Unpaid Care), अनौपचारिक श्रम और सामुदायिक सेवा- पारंपरिक आर्थिक गणनाओं की परिधि से बाहर रहा है। किंतु इस हकीकत को पहचानते हुए, मोदी सरकार ने हमेशा देखभाल के इस 'अदृश्य पहलू' को कम करने, उसे सामाजिक मान्यता देने और उसके न्यायसंगत पुनर्वितरण पर बल दिया है। सरकार का दृष्टिकोण देखभाल से जुड़ी सेवाओं को पेशेवर स्वरूप प्रदान कर उन्हें समावेशी विकास के एक नए 'इंजन' के रूप में रूपांतरित करना है।

भारत में महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर (FLFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है। यह आंकड़ा भारतीय महिलाओं की बढ़ती आकांक्षाओं और आर्थिक गतिविधियों में उनके बढ़ते प्रभुत्व का सूचक है। सवैतनिक कार्यों में महिलाओं की यह भागीदारी न केवल घरेलू समृद्धि का आधार बनती है, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाती है।

आर्थिक सर्वेक्षण इस वास्तविकता को रेखांकित करता है कि यदि हम 'अवैतनिक देखभाल' के बोझ को कम कर सकें और इन सेवाओं को एक व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करें, तो महिला रोजगार के परिदृश्य में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। भारतीय 'केयर इकोनॉमी' वर्तमान में ही लाखों लोगों की आजीविका का संबल है, और आने वाले दशक में इसमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएँ हैं।

यही कारण है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में 'केयर इकोनॉमी' को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है। 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' (Women-led Development) के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता ऐतिहासिक 'जेंडर बजट' में स्पष्ट झलकती है, जिसका आवंटन अब तक के उच्चतम स्तर-5 लाख करोड़ रुपये से अधिक पर पहुँच गया है। सरकार के समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत, हम 1.5 लाख देखभालकर्ताओं के कौशल विकास में निवेश कर रहे हैं, कामकाजी महिला छात्रावासों का विस्तार कर रहे हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाकर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही, स्वास्थ्य एवं पोषण प्रणालियों के समन्वय को भी सशक्त किया जा रहा है। ये सभी प्रयास एक स्पष्ट राजनीतिक और नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं- जब महिलाओं को आवश्यक सहयोग और मंच मिलता है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गति तीव्र हो जाती है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता जैसे वैधानिक ढांचे शिशु देखभाल केंद्रों और श्रमिक कल्याण के प्रावधानों को सुदृढ़ करते हैं। ये सुधार एक गहरे सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं- शिशु देखभाल सहायता कोई गौण विकल्प या सुविधा मात्र नहीं, बल्कि यह आर्थिक न्याय का एक अनिवार्य संरचनात्मक आधार है।

हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के केन्द्र में रखती है, जो देश की कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं। अतः उनका सर्वांगीण कल्याण एक अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है। वर्ष 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे परिवार के भीतर भी देखभाल से जुड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। साथ ही, करोड़ों बच्चों को उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों के दौरान- जब सीखने की क्षमता और भविष्य की उत्पादकता की नींव रखी जाती है- व्यवस्थित प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, सुदृढ़ पोषण और स्वास्थ्य सहायता की नितांत आवश्यकता होगी।

तेजी से होते शहरीकरण, प्रवासन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने हमारी पारंपरिक सामाजिक सहायता प्रणालियों को बुनियादी रूप से बदल दिया है। अनौपचारिक ढांचों पर बढ़ते दबाव के कारण अब सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिशु देखभाल व पारिवारिक सेवाओं की आवश्यकता अनिवार्य होती जा रही है। संगठित और सामुदायिक सेवाओं की यह मांग केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शहरों (Tier-2 & 3 Cities) और ग्रामीण जनपदों में भी तीव्रता से उभरेगी।

देखभाल की अर्थव्यवस्था में निवेश एक साथ कई राष्ट्रीय लक्ष्यों को मजबूत करता है। इससे महिला श्रमशक्ति की भागीदारी बढ़ती है, बाल विकास के परिणाम सुधरते हैं, बुजुर्गों का कल्याण सुनिश्चित होता है और गरिमापूर्ण रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। देखभाल प्रणालियों के संस्थागत और पेशेवर होने से महिलाएँ सशक्त होती हैं, परिवारों को स्थिरता मिलती है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होती है।

जैसे-जैसे भारत 'अमृतकाल' से 'विकसित भारत @2047' की ओर बढ़ रहा है, हम इस परिवर्तनकारी सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि सामाजिक बुनियाद को सुदृढ़ किए बिना विकास को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता- और केयर इकॉनमी ही वह अनिवार्य आधार है।

इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, हम देखभाल के अदृश्य श्रम को सम्मान देने और उसे संस्थागत रूप से सशक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकसित भारत' का हमारा दृष्टिकोण केवल बोर्डरूम एवं संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सशक्त देखभाल प्रणालियों पर आधारित है, जो महिलाओं के विकल्पों, गरिमा और आर्थिक सामर्थ्य का विस्तार करती हैं।

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, भारत सरकार की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं)

भारत में महिलाओं के प्रति बदलने लगा है नजरिया

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने, बाधाओं को तोड़ने और सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज और राष्ट्र मजबूत होते है। यह समानता और अधिकारों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, जो महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक है। यह एक ऐसा दिन है जो महिलाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साल 1911 से हर साल 8 मार्च पूरे विश्व में मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम है दान से लाभ है, जो उदारता, सहयोग और सामूहिक प्रगति के मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह अभियान इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं का समर्थन करना और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना सभी के लिए व्यापक सामाजिक और आर्थिक लाभ ला सकता है। इस अभियान का मूल विचार यह है कि जब महिलाएं शिक्षा, नेतृत्व, उद्यमिता, विज्ञान, कला और राजनीति जैसे क्षेत्रों में सशक्त होती हैं, तो इससे मजबूत समुदाय और साझा समृद्धि का निर्माण होता है। सहयोग और समान अवसरों को प्रोत्साहित करके, यह अभियान समाज में समावेशी विकास और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देना चाहता है।

भारत में महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। अगर हम इक्कीसवीं सदी की बात करे तो यहां की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही है। अब तो भारत की संसद ने भी महिलाओं के लिये लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास कर दिया है। उससे आने वाले समय में भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जायेगी। देश में महिलाओं को अब सेना में भी महत्वपूर्ण पदो पर तैनात किया जाने लगा है। जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रमेश सर्राफ धमोरा

(हि.स)

यहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। महिलायें देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है तथा विकास में भी बराबर की भागीदार है। आज के युग में महिला पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि उनसे दो कदम आगे निकल चुकी है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान जीवन जीने का हक है। भारत में नारी को देवी के रूप में देखा गया है। कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल से ही यहां महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है।

भारत में वर्षो से महिला सुरक्षा से जुड़े कई कानून बने है। इसमें हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पीनल कोड 1860, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, क्रिस्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट 1990, सेक्सुअल हर्रास्मेंट ऑफ वुमन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 आदि। इसके अलावा 7 मई 2015 को लोक सभा ने और 22 दिसम्बर 2015 को राज्य सभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अन्तर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सजा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक साल 2023 में भारत में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,05,861 अपराध दर्ज किए गए। इन अपराधों में बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, और अपहरण जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के सामने आए हैं, जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमारी उदासीनता को दशार्ते हैं। इससे पहले 2022 में 4,45,256 मामले, 2021 में 4,28,278 मामले, 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर से पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिलीं। इसमें 16 हजार से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश राज्य से आए हैं। आंकड़े हैरान कर देने वाली हैं। क्योंकि आयोग में ये शिकायत गरिमा के अधिकार कैटेगरी के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2,411 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 1,343, बिहार में 1,312 और मध्य प्रदेश में 1,165 इतने मामले दर्ज किए गए हैं।

2023 के 12 महीने बाद जारी किए गए इस रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे अपराध दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की यह रिपोर्ट महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता दिखाती है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में यौन उत्पीड़न के 805 मामले, साइबर अपराध के 605 मामले, पीछा करने की 472 मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ 409 शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल 2023 में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के 1,537 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत 8,540, घरेलू हिंसा के 6,274, दहेज उत्पीड़न के 4,797, छेड़छाड़ के 2,349, और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के 1,618 मामले दर्ज किए गए।

2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2022 की तुलना में कम हुए हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 30,864 मामले दर्ज किए गए थे। जबकि 2023 में यह संख्या घटकर 28,278 हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल 2022 के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब 30,864 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो 2014 के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षो में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किये हैं। आज भारत में महिलायें पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है।

हम एक तरफ महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देकर उन्हे आगे बढ़ा रहें है। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आये दिन हमें महिलाओं के साथ बलात्कार, दुर्व्यवहार होने की घटनायें सुनने को मिलती रहती है। ऐसी घटनाओं से महिला सशक्तीकरण के अभियान को धक्का लगता हैं। देश में महिलाओं के प्रति खराब होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं अपितु हर आम आदमी की भी है। हम सभी को आगे आकर महिला सुरक्षा की लड़ाई में महिलाओं का साथ देना होगा तभी देश की मातृ शक्ति सर उठा कर शान से चल सकेगीं। अब महिलाओं को समझना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति समाज में चली आ रही परम्पराओं का परिणाम है। इन परम्पराओं को बदलने का बीड़ा स्वयं महिलाओं को ही उठाना होगा। तभी समाज में उनके प्रति सोच बदल पायेगी।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से सम्बद्ध है।)

मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने श्री आनंदपुर साहिब में विश्व स्तरीय श्री गुरु तेग बहादुर विश्वविद्यालय को मंजूरी दी

ह्यपंजाब उद्योग क्रांतिह्न के तहत औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को हरी झंडी: सरकारी कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की भर्ती होगी

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

राज्य में उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने आज श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की भर्ती को भी हरी झंडी दे दी गई। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार कैबिनेट ने विश्वविद्यालय की स्थापना और ह्यश्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयह्न के लिए ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना समय पर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक फैसले लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

मंत्रिमंडल ने ह्यपंजाब उद्योग क्रांतिह्न के तहत औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति में सेक्टर आधारित नीतियां, विस्तृत योजनाएं और दिशानिर्देश शामिल हैं।

इस नीति का उद्देश्य राज्य में वित्तीय रियायतें, क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक और संरचित व्यवस्था स्थापित करना है। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और पंजाब को उच्च आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान खिलाड़ियों के लिए आरक्षण को अधिक व्यवस्थित बनाने वाली नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत खेल उपलब्धियों के प्रमाण पत्रों को अंक देने के लिए स्पष्ट और सरल मानदंड तय किए गए हैं। नई नीति के अनुसार 75 प्रतिशत महत्व खेल उपलब्धियों को और 25 प्रतिशत महत्व प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन को दिया जाएगा।

कैबिनेट ने ह्यपंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तकनीकी (ग्रुप-सी) सेवा नियम-2016ह्न में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के रूप में शामिल किया गया है। इससे डिप्लोमा धारकों को फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब होमगार्ड के शहीद वालंटियर अशोक कुमार, नंबर 25140/जीएसपी के परिवार को विशेष मामले के रूप में 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेशिया सहायता देने को मंजूरी दी। उन्होंने हाल ही में गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई थी। देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए उनके महान योगदान को मान्यता देते हुए मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने विधान सभा के वर्तमान सत्र में ह्यद पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट, स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल, 2026ह्न पेश करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। इस कदम का उद्देश्य ह्यद पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट, स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) अध्यादेश, 2026ह्न को अधिनियम में बदलना है। एक अन्य बड़े

निर्णय में मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य के सरकारी कॉलेजों में 1,158 असामियों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें 1,091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन शामिल हैं। यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (पी.पी.एस.सी.) के माध्यम से यू.जी.सी. नियम-2018 के अनुसार सख्ती से की जाएगी। सरकार पी.पी.एस.सी. के पास लंबित सहायक प्रोफेसर की 612 असामियों की पूर्व मांग को वापस लेगी और सभी असामियों के लिए नई संयुक्त मांग जमा करवाएगी।

सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर प्रदान करने के लिए, जिनमें वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्होंने 19 अक्टूबर, 2021 के विज्ञापन के तहत आवेदन दिया था, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में एक बार की छूट दी जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार अतिरिक्त आयु छूट मिलेगी।

भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने विश्व स्तरीय एम.आई.सी.ई. (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एक्जीबिशन्स) प्रोजेक्ट और व्यावसायिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक तथा सरकारी आयोजनों के लिए बहु-उद्देशीय ढांचे को मंजूरी दे दी। राज्य में एम.आई.सी.ई. प्रोजेक्ट्स के खर्चों में स्पष्टता की कमी के कारण निवेशकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसे हल करने के लिए, सरकार ने 4 जून, 2025 की अधिसूचना में संशोधन करके एम.आई.सी.ई. प्रोजेक्ट्स को एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया है और व्यावसायिक खर्चों के 50 प्रतिशत पर लागू खर्च निर्धारित किए हैं।

मंत्रिमंडल ने मेडिसिटी नीति-2014 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है ताकि कुछ स्थानों को मौजूदा नीति के माध्यम से और अन्यों को ई-नीलामी के माध्यम से निपटाया जा सके। जिन स्थानों की ई-नीलामी होनी है, उसके लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है। ई-नीलामी स्थानों की कीमत ई-नीलामी प्लॉटों के लिए कीमत निर्धारण नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जबकि नीति के तहत आवंटित साइटें विज्ञापन के समय प्रचलित दरों पर पेश की जाएंगी। हालांकि ई-नीलामी में भागीदारी के लिए योग्यता शर्तों में ढील दी गई है, लेकिन भूमि का उपयोग अस्पताल के उद्देश्यों के लिए सीमित रहेगा। मंत्रिमंडल ने गमाडा द्वारा के-12/सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना के लिए शिक्षा प्लॉटों की आवंटन नीति को भी मंजूरी दे दी।

यह नीति ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत साइटों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (इंडिया) की सिफारिशों पर तैयार की गई है। यह तकनीकी योग्यता मापदंड पेश करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक और सक्षम शैक्षिक संस्थान ही ग्रेटर मोहाली क्षेत्र में स्कूल विकास के लिए भूमि प्राप्त कर सकें, जिसमें एसएएस नगर (मोहाली), न्यू चंडीगढ़ और एरोसिटी शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पेश की गई मूल्यांकन रिपोर्टों और ग्लाडा के निरीक्षणों के आधार पर ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) की संपत्तियों की कीमतों को तर्कसंगत बनाने को भी मंजूरी दे दी। संशोधित दरें ई-नीलामी के लिए आधार रिजर्व कीमतों के रूप में काम करेंगी, जिसकी आवंटन प्रचलित ई-नीलामी नीति के अनुसार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को किया जाएगा। ये दरें एक कैलेंडर वर्ष के लिए वैध रहेंगी और उसके बाद मौजूदा विभागीय नीति के अनुसार संशोधित की जाएंगी। पंजाब कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के आश्रित दिव्यांग भाई-बहनों को शामिल करके पारिवारिक पेंशन को परिभाषित करने के लिए ह्यपंजाब सिविल सेवाएं नियम, भाग-2 के नियम 6.17 (3) ह्नमें संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इसके अनुसार, ऐसे आश्रित परिवार के सदस्य अब पारिवारिक पेंशन के लाभ के हकदार होंगे।

मोहिंदर भगत द्वारा बागवानी परियोजनाओं की प्रगति संबंधी अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के बागवानी क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में काम करते हुए बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कल शाम बागवानी विभाग की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ पंजाब भवन, चंडीगढ़ में एक विशेष समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर बागवानी प्रशासनिक सचिव अरशदीप सिंह थिंद, निदेशक बागवानी मनीष कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे।

बैठक के दौरान मंत्री ने बागवानी क्षेत्र के विकास और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए चल रही योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर की बागवानी नर्सरियों में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर उच्च किस्म के पौधे उपलब्ध करवाए जा सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्रीय स्तर पर नियमित दौरा करें, किसानों से सीधी बातचीत करें और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करें।

इस दौरान जिला बागवानी अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित मुश्किलों और आवश्यकताओं के बारे में मंत्री को अवगत करवाया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बागवानी नर्सरियों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तुरंत भेजी जाए ताकि जरूरी कदम जल्दी उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि बागवानी के विकास के लिए आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। मंत्री ने टेंडर प्रक्रिया से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता देने के लिए कहा और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएं। किसानों को दी जा रही सब्सिडी के मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सब्सिडी से संबंधित सभी मामलों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके। इस बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन रणबीर सिंह, निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गुरजीत सिंह, मुख्य भूमिपाल मोहिंदरजीत सैनी, निदेशक पनसीड जसवंत सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि (इंजी.) जगदीश सिंह, संयुक्त निदेशक हरमेल सिंह, गुरसरन सिंह तथा उप निदेशक हरप्रीत सेठी एवं अन्य जिला अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

सिविल सेवाओं परीक्षा में सुनवर्दीप सिंह की सफलता युवाओं के लिए प्रकाश स्तंभ: कुलतार सिंह संधवां

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

पंजाब विधान सभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवां ने यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने वाले देश के सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को दिल से बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की बेटियों और बेटों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।

उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि पटियाला की सिमरनदीप कौर और रसनीत कौर, बलाचौर की कृतिका चौधरी, मानसा से मनप्रीत कौर और आकृति सिंगला जैसे हीरे ने पूरे देश में पंजाब का नाम चमकाया है।

उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह बहुत गर्व और खुशी की बात है कि फरीदकोट निवासी डॉ. कुलदीप सिंह (डायरेक्टर, पी.ए.यू., फरीदकोट) के पुत्र सुनवर्दीप सिंह ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं परीक्षा में 76वां रैंक प्राप्त किया है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए पंजाब विधान सभा स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि सुनवर्दीप सिंह की यह शानदार सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे फरीदकोट जिले और समूचे पंजाब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है, जो साबित करती है कि कड़ी मेहनत, लगन और मजबूत इरादों से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। संधवां ने कहा कि आज के समय में युवाओं को सुनवर्दीप सिंह की सफलता से सीखने की जरूरत है। विद्यार्थियों को समाज की तरक्की के लिए योगदान देना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुनवर्दीप सिंह जैसे प्रतिभाशाली युवा समाज के लिए प्रकाश स्तंभ सिद्ध होते हैं, जो न केवल खुद आगे बढ़ते हैं बल्कि दूसरों को भी ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं। स्पीकर संधवां ने डॉ. कुलदीप सिंह और उनके परिवार को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी और सुनवर्दीप सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

संक्षिप्त-समाचार

गमाडा ने ई-नीलामी में कमाए लगभग 3137 करोड़ रुपये: हरदीप सिंह मुंडियां

चंडीगढ़। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा आयोजित संपत्तियों की ई-नीलामी, जो शुक्रवार देर रात समाप्त हुई, को निवेशकों से भरपूर उत्साह मिला है। इस ई-नीलामी से गमाडा को कुल 3136.97 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह ई-नीलामी 14 जनवरी, 2026 को शुरू हुई थी। ई-नीलामी के लिए प्रस्तुत की गई कुल 42 संपत्तियों में से 37 संपत्तियों की सफल बोली लगी। आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि लगभग 90 प्रतिशत संपत्तियों के लिए बोली प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि 2018.84 करोड़ रुपये की आरक्षित कीमत वाली इन साइटों को 3136.97 करोड़ रुपये में बेचा गया, जो एक ही ई-नीलामी में गमाडा द्वारा अब तक प्राप्त किया गया सबसे अधिक राजस्व है। स. हरदीप सिंह मुंडियां ने ई-नीलामी की इस सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की निवेशक-पक्षीय नीतियों को देते हुए कहा कि लगातार सफल ई-नीलामियों के कारण राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि संपत्तियों की कीमतों को यथार्थवादी बनाना और बाजार के अनुसार मूल्य निर्धारण करना भी इस नीलामी को अच्छा उत्साह मिलने का एक प्रमुख कारण रहा है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नीलामी से प्राप्त राजस्व को विकास प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में विकास कार्यों के नए मानक स्थापित करने के लिए खर्च करेगा।

10,000 रुपये रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक को विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों किया काबू

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सी.आर.सी. शाखा, एस.एस.पी. कार्यालय बरनाला में तैनात वरिष्ठ सहायक दविंदर सिंह को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। यहां यह जानकारी साझा करते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव दानगढ़, जिला बरनाला के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता पंजाब पुलिस में सहायक सब-इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है और उसने अपनी सेवा अवधि में विस्तार (सेवा बढ़ाने) के लिए आवेदन किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी वरिष्ठ सहायक दविंदर सिंह ने उसकी सेवा अवधि बढ़ाने में मदद करने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की। हालांकि शिकायतकर्ता ने रिश्वत देकर अपना काम करवाना उचित नहीं समझा और इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो रेंज, पटियाला में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी वरिष्ठ सहायक दविंदर सिंह को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना पटियाला में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

यूं.पी.एस.सी.में जैतो के आशुतोष गर्ग ने 479वां रैंक हासिल किया

जैतो। यूं.पी.एस.सी. सिविल सर्विसेज परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2025 शुक्रवार को जारी हुआ । जिसमें जैतो के आशुतोष गर्ग पुत्र प्रदीप कुमार गर्ग ने 479वां रैंक हासिल कर अपने परिवार व शहर का नाम रौशन किया है।2020 में आशुतोष गर्ग की बहन ने भी यू.पी.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं। आशुतोष गर्ग ने बताया कि वह आजकल बठिंडा में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि वह 2016 से इस कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बाद में इसकी तैयारी छोड दी लेकिन बहन आसमा गर्ग जो यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं के कहने और माता-पिता के सहयोग से उन्होंने पिछले 3 साल से फिर इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और इस बार उन्होंने 479वां रैंक हासिल कर लिया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, बहन आसमा गर्ग व पत्नी सोनिया गर्ग व पूरे परिवार को दिया है। इस बीच पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल जैतो , राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित रघुनंदन पराशर, पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शैली गर्ग व नरेश जिंदल बालाजी आयल वालों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक आदि व गणमान्य नागरिक ने आशुतोष गर्ग व उनके परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं है।

गैंगस्टरां ते वार का 46वां दिन: पंजाब पुलिस ने 471 ठिकानों पर की छापेमारी; 163 गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों के तहत शुरू की गई निर्णायक मुहिम ह्यगैंगस्टरां ते वारह्न के 46वें दिन पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिह्नित और मैप किए गए 471 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरां ते वार - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।

शिरोमणि कमेटी यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले सिख स्टूडेंट्स को 1-1 लाख रुपये देकर सम्मानित करेगी: एडवोकेट धामी

जैतो। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने यू.पी.एस.सी. परीक्षा पास करके हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए चुने गए सिख स्टूडेंट्स को बधाई दी है और ऐलान किया है कि शिरोमणि कमेटी उन्हें 1 लाख रुपए देकर सम्मानित करेगी। शनिवार को ऑफिस से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में एडवोकेट धामी ने कहा कि यू.पी.एस..सी. जैसी मुश्किल परीक्षा में कामयाबी हासिल करना युवाओं की कड़ी मेहनत, लगन और पक्के इरादे की निशानी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स सिमरनदीप कौर और सनवरदीप सिंह समेत दूसरे सिख स्टूडेंट्स ने यूं.पी.एस.सी. कॉम्पिटिटिव परीक्षा पास करके न सिर्फ अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि यह सिख कम्युनिटी के लिए भी गर्व की बात है।उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश भर में 15वीं पोजीशन हासिल करने वाली लड़की सिमरनदीप कौर खालसा कॉलेज पटियाला की स्टूडेंट है, जिसे शिरोमणि कमेटी चलाती है।

एडवोकेट धामी ने कहा कि शिरोमणि कमेटी सिख स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि शिरोमणि कमेटी तो यू.पी.एस.सी. एग्जाम पास करने वाले सिख स्टूडेंट्स को एक-एक लाख रुपये की रकम देकर सम्मानित करेगी। शिरोमणि कमेटी प्रेसिडेंट ने कहा कि शिरोमणि कमेटी हमेशा से युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश करती रही है और भविष्य में भी इसी तरह एक्टिव रहेगी। उन्होंने खास तौर पर बताया कि शिरोमणि कमेटी के आने वाले बजट में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एक खास रकम रखी जाएगी, जिससे जरूरतमंद गुरसिख बच्चों को इस फील्ड में मदद की जाएगी।

पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 14.16 करोड़ जारी किए: डॉ. बलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आशीर्वाद योजना के तहत 2,777 पात्र लाभार्थियों को कुल ₹14.16 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की है। यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे अपनी बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक कर सकें।

उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से श्री अमृतसर साहिब, बरनाला, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन सहित 15 जिलों से प्राप्त आवेदनों में से 2,777 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की गई है। कैबिनेट मंत्री ने जिला-वार विवरण देते हुए बताया कि श्री अमृतसर साहिब में 351, बरनाला में 37, फरीदकोट में 59, श्री फतेहगढ़ साहिब में 46, गुरदासपुर में 523, होशियारपुर में 354 और जालंधर में 24 लाभार्थियों को योजना के तहत सहायता दी गई है।

इसी प्रकार लुधियाना में 62, मोगा में 42, श्री मुक्तसर साहिब में 107, पटियाला में 519, एस.ए.एस. नगर में 79, संगरूर में 164, मलेरकोटला में 155 और तरनतारन में 255 लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे परिवार इस महत्वपूर्ण अवसर को सम्मान और खुशी के साथ मना सकें।

उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित हो रही है, जिससे वे अपनी बेटियों का विवाह सम्मान और आत्मसम्मान के साथ कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदनों की प्रक्रिया आशीर्वाद पोर्टल पर सेवा केंद्रों के माध्यम से पारदर्शी और सरल तरीके से जारी रखी जाए, ताकि पात्र परिवारों को बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और वह बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में आता हो। परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए और योजना के तहत एक पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटियां लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (उइळ) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है।

ह्यपंजाब शिक्षा क्रांतिह्न के तहत प्रिंसिपलों को सिंगापुर भेजकर शिक्षण के बेहतरीन वैश्विक तरीकों को कक्षा तक लाया जा रहा है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को रवाना किया, अब तक 234 प्रिंसिपल विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भेजे गए

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज सिंगापुर की प्रिंसिपल अकादमी में प्रशिक्षण के लिए 30 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के आठवें बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को वैश्विक शिक्षा पद्धतियों से परिचित कराना और राज्य की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 का कड़ा विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, कांग्रेस और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ह्यएक्सह्न पर लिखा, आज पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों का एक और बैच प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर रवाना हुआ। मैंने इस अवसर पर उनसे मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दीं और यात्रा की सफलता के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने आगे लिखा, हमारी सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। इसी दृष्टिकोण के तहत हम अपने शिक्षकों और प्रिंसिपलों को लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर रहे हैं, ताकि वे नए और आधुनिक तरीके सीख सकें और पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकें। हमारा लक्ष्य केवल स्कूल बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है जो पंजाब के हर बच्चे को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के योग्य बनाए।

मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करने के लिए 30 प्रिंसिपलों का आठवां बैच 8 से 14 मार्च तक सिंगापुर की प्रिंसिपल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। अब तक 234 प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों के आठ बैचों को प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा चुने गए प्रिंसिपलों का सत्यापन किया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ये प्रिंसिपल विदेशों में प्रचलित आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से परिचित होते हैं। वापसी के बाद वे इन अनुभवों को अपने विद्यार्थियों और सहयोगियों के साथ साझा करते हैं, ताकि छात्र वैश्विक स्तर की शिक्षा का सामना कर सकें। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर रही है।

अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सुखबीर सिंह बादल जमीनी हकीकत से दूर हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए हवाई किले बना रहे हैं। पंजाब के लोग ऐसे नेताओं के पिछले रिकॉर्ड से अच्छी तरह परिचित हैं और उन्हें राज्य को बर्बाद करने का एक और मौका कभी नहीं देंगे।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मतदाता सूची विवाद पर ममता बनर्जी लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भाजपा और चुनाव आयोग पर साधा निशाना

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

फोटोः हि.स.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर शनिवार को लगातार दूसरे दिन कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठी हैं। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर बंगाल के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

धरना कार्यक्रम चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के प्रस्तावित कोलकाता दौरे से ठीक पहले शुरू हुआ है। यह धरना प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जल्दबाजी और अव्यवस्थित तरीके से की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और चुनाव आयोग की कथित साजिश को जनता के सामने उजागर किया जाएगा।

धरना मंच पर तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, बुद्धिजीवी, कलाकार और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अंतिम सूची में लाखों नाम हटाए जाने और बड़ी संख्या में मतदाताओं को निर्णयाधीन श्रेणी में रखने से आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है।

ममता का भाजपा पर हमला- बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को धर्मतला के मेट्रो चैनल पर जारी अपने धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बंगाल को कमजोर करने की कोशिश की गई तो दिल्ली की सरकार गिरा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा सावधान रहे। वोट काटकर बंगाल को विभाजित नहीं किया जा सकता। बंगाल लड़ रहा है और लड़ना जानता है। ज्यादा कुछ किया तो दिल्ली की सरकार गिरा देंगे। धरना मंच से उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और भाजपा डराने-धमकाने की राजनीति कर रही है। ममता ने कहा कि कई लोगों को पद से हटाने या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। मुख्यमंत्री ने हाल में राज्यपाल को हटाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले राज्यपाल को बदलने का निर्णय समझ से परे है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे लोग अहंकार में हैं और सत्ता सहयोगी दलों के सहारे चल रही है। खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि चंद्रबाबू की दया पर सरकार चल रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता के मुद्दों पर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। धरना मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के नेता अजीत पवार का भी उल्लेख किया और कहा कि जिस मामले में उन्होंने पहले निष्पक्ष जांच की मांग की थी, वह अब सही साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री का यह धरना चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के विरोध में शुरू किया गया है और राजनीतिक हलकों में इसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को शुरू हुआ यह धरना शनिवार को दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है।

लगभग 9.95 लाख रुपये की कीमती वस्तुएं और नशीले पदार्थ के साथ पांच लोग गिरफ्तार

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
भागलपुर

रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अपराध और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार निगरानी और विशेष अभियानों के तहत मालदा मंडल की रेलवे सुरक्षा बल ने मनीष कुमार गुप्ता मंडल रेल प्रबंधक मालदा के मार्गदर्शन और अशिम कुमार कुल्लू मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ के पर्यवेक्षण में किए गए अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।

एक विशेष अभियान के दौरान सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों ने पैसेंजर्स की संपत्ति की चोरी में शामिल पांच (05) व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से सोने और चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन, नकदी और चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए गए विभिन्न उपकरण जैसे ब्लेड, चाकू, प्लायर, कटर और स्क्रूड्राइवर बरामद किए गए। बरामद वस्तुओं का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 7,60,000 रुपया है। उधर ऑपरेशन नार्कोस के तहत किए गए एक अन्य अभियान में मालदा के आरपीएफ क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच के अधिकारी और कर्मचारी आरपीएफ पोस्ट बरहरवा के साथ मिलकर तीनपहाड़ रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान ट्रेन संख्या 13032 जयनगर झ हावड़ा एक्सप्रेस के एक जनरल कोच से संदिग्ध मादक पदार्थ (गांजा) से भरा एक अनक्लेम्ड बैग बरामद किया। जांच के दौरान बैग के अंदर लगभग 4.7 किलोग्राम वजन के चार पैकेट पाए गए, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 2,35,000 रुपया है। कुल मिलाकर, इन अभियानों के दौरान 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और आभूषण, मोबाइल फोन, नकदी, चोरी के उपकरण और संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद किए गए। गिरफ्तार व्यक्तियों और बरामद सामग्री को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जीआरपी अधिकारियों को सौंप दिया गया।

तमिलनाडु में 108 एम्बुलेंस सेवा अब व्हाट्सऐप से उपलब्ध

- चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन

एजेंसी (हि.स.)
चेन्नई

फोटोः हि.स.

तमिलनाडु में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। अब आम लोग 108 एम्बुलेंस सेवा को केवल एक व्हाट्सऐप मैसेज के माध्यम से भी बुला सकते हैं। इस नई सुविधा का उद्देश्य आपातकालीन कॉल सेंटर पर बढ़ते दबाव को कम करना और लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

इस सेवा का उद्घाटन शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमणियन ने किया। इसके तहत लोग तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम प्रोजेक्ट के आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर 94450 30725 पर ह्लएचआईह्व भेजकर एम्बुलेंस सेवा का अनुरोध कर सकते हैं। जैसे ही उपयोगकर्ता ह्लएचआईह्व भेजता है, उसे उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की एक सूची दिखाई देती है। इसमें से ह्लबुक एम्बुलेंसह्व विकल्प चुनने के बाद उपयोगकर्ता को ह्लसेंड लोकेशनह्व के माध्यम से अपनी वर्तमान लोकेशन साझा करनी होती है। लोकेशन साझा करने के बाद सिस्टम में अनुरोध दर्ज हो जाता है और उपयोगकर्ता को एक इंसिडेंट आईडी प्राप्त होती है। इसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर की ओर से कॉल करके एम्बुलेंस भेजने की पुष्टि की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया से एम्बुलेंस सेवा को और अधिक तेज और सुगम बनाया गया है। इस व्हाट्सऐप चैटबॉट सुविधा में एम्बुलेंस वाहन की जानकारी, नजदीकी सरकारी अस्पताल की जानकारी, एम्बुलेंस की लाइव ट्रैकिंग तथा सेवा की वर्तमान स्थिति से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे मरीज और उनके परिजनों को एम्बुलेंस की स्थिति का पता चलता रहेगा और सेवा में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसी अवसर पर चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में भी कई आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार के बजट 2024झ2025 के तहत लगभग 3.80 करोड़ रुपये की लागत से उच्च गुणवत्ता वाली वेस्कुलर सी-आर्म मशीन और हाइब्रिड वेस्कुलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए गए हैं। इन अत्याधुनिक सुविधाओं के माध्यम से एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग और एंडोवास्कुलर एनेयूरिज्म जैसे जटिल उपचार अब कम चीरे के साथ किए जा सकेंगे। इससे मरीजों में जटिलताओं और रक्तस्राव का खतरा कम होगा, रेडिएशन का प्रभाव घटेगा और मरीज जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों के उपचार के लिए स्पाइन एंडोस्कोपी नामक आधुनिक और न्यूनतम चीरे वाली तकनीक भी शुरू की गई है।

कांग्रेस की गठबंधन बनाने की 'आखिरी कोशिश भी विफल': अखिल गोगोई

एजेंसी (हि.स.)
गुवाहाटी

फोटोः हि.स.

असम में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इस बीच सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने-अपने गठबंधन को बड़ा स्वरूप देने के लिए भी कमर कस रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन तैयार करने में लगातार विफलता का सामना करना पड़ा रहा है। एक समय विपक्षी खेमे में लगभग 10 पार्टियां थीं, वहीं आज मुख्य रूप से चार पार्टियों तक गठबंधन सिमटता नजर आ रहा है।

कांग्रेसी गठबंधन से भाव न मिलने पर रायजोर दल के प्रमुख एवं शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि 'सर्वशेष्ठ चेष्टाओ व्यर्थ' (आखिरी कोशिश भी विफल)। इस छोटी सी बात ने राजनीतिक हलकों में कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन के बारे में बातचीत की स्थिति के बारे में विराम लगाने की अटकलों को हवा दे दी है। रायजोर दल प्रमुख का यह विचार ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों ने घोषणा की है कि वे पूरे राज्य में संयुक्त प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वहीं एक संवाददाता सम्मेलन में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष एवं सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि पार्टी अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट), असम जातीय परिषद और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर एक बड़ा विपक्षी मोर्चा बनाने पर काम कर रही है। गौरव गोगोई ने कहा कि अखिल गोगोई की नेतृत्व वाली रायजोर दल समेत दूसरी पार्टियों के साथ भी बातचीत चल रही है, और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में यह ग्रुप और बढ़ेगा। साथ ही संयुक्त रूप से प्रचार अभियान चलाने की बात कही। लेकिन, गौरव के इस मंसूबे पर पानी फिरता नजर आ रहा है।

विपक्षी गठबंधन ने अभी तक अपनी सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया है, हालांकि कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की उम्मीद है। कांग्रेस ने पहले ही 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस गठबंधन में शामिल एजेपी के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई ने कहा है कि चारों पार्टियों ने यह मैसेज देने के लिए हाथ मिलाया है कि वे भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपनी कोशिश में एकजुट हैं। जबकि, सीपीआई (एम) के राज्य सचिव सुप्रकाश तालुकदार ने गठबंधन को एक 'अच्छी शुरूआत' बताया।

संक्षिप्त-समाचार

चाय बागान में जंगली हाथियों के हमले में मां और बेटे की मौत

तिनसुकिया (असम)। उपरी असम के तिनसुकिया जिलांतर्गत ब्रह्मजान चाय बागान इलाके में बीती रात जंगली हाथियों के हमले में एक महिला एवं उसके पुत्र की मौत हो गयी। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि बीती देर रात एक चाय बागान में जंगली हाथियों के झुंड ने प्रवेश कर एक घर पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला और उसके बेटे की मौत हो गई। यह घटना दुमदुमा फॉरेस्ट डिवीजन के पेंगरी इलाके में ब्रह्मजान चाय बागान में हुई, जब हाथियों का एक झुंड श्रमिकों के लाइन में घुस गया, जिसके चलते वहां रहने वालों में दहशत फैल गई। सूचना के अनुसार, हाथियों ने चाय बागान में काम करने वाले बुधन रौतिया (50) और उनकी मां अनीता रौतिया (70) के घर पर हमला किया। दोनों को उनके घर के अंदर ही हाथियों ने पैरों तले कुचलकर मार डाला। बताया गया है कि यह घटना आधी रात के आसपास हुई जब झुंड चाय बागान इलाके में भोजन की तलाश में प्रवेश कर गया और घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि हाथी कई दिनों से इस इलाके में घूम रहे थे, जिससे गांव वालों और चाय बागान में काम करने वालों में दहशत का माहौल कायम था। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि इलाके में हाथियों की आवाजाही के बारे में बार-बार की गई शिकायतों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने दावा किया कि दुमदुमा फॉरेस्ट डिवीजन के पेंगरी में खटांगपानी फॉरेस्ट रेंज के कई इलाकों में इंसान-हाथी टकराव बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाथियों के बार-बार आने के बावजूद, वन विभाग ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए असरदार कदम उठाने में नाकाम रहा है। बाद में वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

कोलकाता में विस्फोट से दहशत, बंद क्लब में धमाके से उड़ी टिन की छत

कोलकाता। शहर के पाइकपाड़ा इलाके में शनिवार तड़के एक बंद पड़े क्लब में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों से इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना पाइकपाड़ा के गांगुलीपाड़ा लेन में हुई, जहां सुबह करीब 6 बजकर 11 मिनट पर जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि क्लब की टिन की छत उड़कर पास की एक बहुमंजिला इमारत की छत पर जा गिरी। स्थानीय लोगों के अनुसार, लगातार कम से कम पांच बार जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि क्लब का दरवाजा और टिन की छत उखड़कर दूर जा गिरी थी और अंदर आग लगी हुई थी। घटना से घबराए लोगों ने तुरंत चितपुर थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को भी जांच के लिए बुलाया गया। स्थानीय निवासियों का दावा है कि जहां विस्फोट हुआ, वहां पहले एक क्लब संचालित होता था, जो पिछले छहझ्रसात महीनों से बंद पड़ा था। उनका कहना है कि क्लब और उससे सटे इलाके में प्रमोटिंग को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ लोगों का संदेह है कि इसी विवाद के चलते किसी ने परित्यक्त क्लब भवन में बम छिपाकर रख दिए थे। घटना के बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत इलाके में पुलिस तैनाती बढ़ाने और क्लब परिसर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में कोलकाता के बीचोंबीच हुए इस विस्फोट की घटना से लोगों में स्वाभाविक रूप से चिंता और भय का माहौल बन गया है।

सीवान में पुलिस गश्ती दल की थार को पिकअप ने मारी टक्कर, सब इंस्पेक्टर समेत तीन घायल

सीवान। सीवान जिले के जीरादेई थाना क्षेत्र में शुक्रवार की मध्यरात्रि सड़क हादसे में पुलिस गश्ती दल की थार गाड़ी पलट गई। घटना में सब इंस्पेक्टर सहित तीन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक जवान बाल-बाल बच गया। जानकारी के अनुसार जीरादेई थाने के खरगी रामपुर गांव के समीप तिराहे पर रात करीब साढ़े बारह बजे गश्ती दल की थार गाड़ी खड़ी थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक पिकअप वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना में पूर्वी चंपारण के अमुआ निवासी राम निवास जायसवाल के पुत्र सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार, जीरादेई थाना के चालक सुरेश कुमार तथा गोरेयाकोठी थाना क्षेत्र के काला डुमरा गांव निवासी गृह रक्षक बल के जवान अशोक कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गाड़ी में सवार एक अन्य जवान नंदलाल को खरोंच तक नहीं आई। सूचना मिलने पर जीरादेई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार ने बताया कि वे लोग रात में गश्त के दौरान खरगी रामपुर तिराहे पर गाड़ी खड़ी कर चौकसी कर रहे थे। तभी पीछे से तेज गति में आए पिकअप ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। गाड़ी पलटने के बाद उन्होंने किसी तरह बाहर निकलकर चालक और जवान को गाड़ी से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई है। हालांकि घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में तरह-तरह की चर्चाएं भी सुनने को मिल रही हैं, जिससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पिकअप वाहन की तलाश में जुटी हुई है।

मंत्री उदय प्रताप सिंह को कोर्ट का नोटिस, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप

जबलपुर। मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री के खिलाफ जबलपुर के न्यायालय ने शुक्रवार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामला तिरंगा ध्वज के अपमान से जुड़ा हुआ है। मामला नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव निवासी कोशल द्वारा दायर परिवाद पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2024 आयोजित एक तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का अनादर किया गया। विशेष न्यायालय(सांसद/ विधायक मामले) ने मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को 7 अप्रैल 2026 को पेश होने निर्देश दिए है। न्यायधीश डी पी सूत्रकार की कोर्ट ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, इसके साथ ही कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के अपराध में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश क्यों न दिया जाए।

राजस्थान में सुबह भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता

जयपुर। राजस्थान में शनिवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। भूकंप का सबसे ज्यादा असर सीकर जिले और आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। हालांकि झटके हल्के होने के कारण कहीं से भी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र जयपुर से करीब 69 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम दिशा में धरती से लगभग पांच किलोमीटर की गहराई में था। सुबह करीब 6:30 बजे आए इस भूकंप के झटके कुछ सेकेंड तक ही महसूस हुए। जानकारी के अनुसार सीकर जिले के खाटूश्यामजी, पलसाना, धींगपुर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने धरती में हल्का कंपन महसूस किया। करीब एक-दो सेकेंड तक झटके महसूस होने से लोग घरों से बाहर निकल आए। पलसाना क्षेत्र के कई लोगों ने बताया कि भूकंप के दौरान उनके घरों के खिड़की-दरवाजे भी हिलने लगे थे।

स्वामीनारायण मंदिर परिसर के बाथरूम में दो कॉलेज छात्राओं के शव बरामद

एजेंसी (हि.स.)
सूरत

फोटोः हि.स.

गुजरात के सूरत के डिंडोली इलाके में सणिया कणदे रोड स्थित आत्मीय संस्कारधाम स्वामीनारायण मंदिर परिसर के बाथरूम से दो युवतियों के शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उधना स्थित सिटीजन कॉलेज में अध्ययनरत 18 वर्षीय रोशनी शरद शिरसाठ और 20 वर्षीय जोसना अतुल चौधरी सुबह घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थीं। लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोग चिंतित हो गए।

परिजनों ने दोनों छात्राओं से कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक फोन नहीं उठाया गया। इसके बाद परिवारजन उनकी तलाश में जुट गए। इसी दौरान डिंडोली क्षेत्र के सणिया कणदे रोड स्थित आत्मीय संस्कारधाम स्वामीनारायण मंदिर के बाथरूम में दोनों छात्राओं के शव संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही डिंडोली पुलिस का काफिला मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने मौके पर निरीक्षण करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिंडोली पुलिस के अनुसार, प्राथमिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होने की संभावना है। इस घटना के बाद डिंडोली इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

स्वस्थ भारत के संकल्प को जन औषधि परियोजना दे रही सार्थक रूप : रेखा गुप्ता

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार के 'स्वस्थ भारत' के संकल्प को आज जन औषधि परियोजना धरातल पर सार्थक रूप दे रही है। केंद्र सरकार का यह दूरदर्शी प्रयास सुनिश्चित करता है कि देश का कोई भी नागरिक, विशेषकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवार, आर्थिक अभाव के कारण आवश्यक उपचार से वंचित न रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ और किफायती बनाना ही योजना का मूल ध्येय है।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आज जन औषधि दिवस के मौके पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में संचालित 620 से अधिक जन औषधि केंद्र आज लाखों परिवारों के लिए बड़ा संबल बन चुके हैं। उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराकर ये केंद्र बीमारियों से लड़ने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं और साथ ही आम जन की गाढ़ी कमाई की बचत भी सुनिश्चित कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में आई यह सकारात्मक पहल समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार पहुंचाने का कार्य कर रही है।

दिव्यांग बेटे की गला दबाकर हत्या का आरोप, पिता गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति को अपने दिव्यांग बेटे की गला दबाकर हत्या करने और शव को तालाब किनारे दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार घटना मेमारी थाना क्षेत्र के मंडल ग्राम की है। आरोपित की पहचान सोनालाल मांडी के रूप में हुई है, जिसे शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया।

बताया गया है कि उसका बेटा सूर्य मांडी जन्म से ही दृष्टिहीन था और उसके हाथ-पैर भी सामान्य रूप से काम नहीं करते थे। बच्चे की विशेष स्थिति के कारण परिवार को उसकी देखभाल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जन्म के कुछ महीनों बाद ही उसकी मां उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। कुछ समय तक बच्चा अपनी नानी के पास रहा, लेकिन नानी की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दादी पर आ गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद से ही आरोपित पिता बच्चे को बोझ मानने लगा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने पहले अपने बेटे को अनाथालय भेजने की भी कोशिश की थी। जब इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने हत्या की योजना बना ली। पुलिस के अनुसार बुधवार को सोनालाल मांडी अपने बेटे को मेमारी के बरापलाशन क्षेत्र स्थित कालदिघी तालाब के किनारे ले गया। वहां उसने बेटे का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब किनारे दफना दिया। हालांकि अगले दिन सुबह तालाब का पानी बढ़ने से मिट्टी बह गई और शव बाहर आ गया। स्थानीय लोगों की नजर पड़ने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

महंगाई पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच एलपीजी सिलेंडर महंगा

घरेलू सिलेंडर पर 60 और वाणिज्यिक 114.5 रुपये बढ़े

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आयात होने वाली तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये की वृद्धि की गई है। नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अब गैर-सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। यह पिछले 11 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की वृद्धि की गई थी। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजार में तेजी के कारण गैस की लागत बढ़ी है, जिसके चलते कीमतों में यह बढ़ोतरी की गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आयात होने वाली तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति पर पड़ रहे असर को भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। आईओसी के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरों के आधार पर एलपीजी की कीमतों में अंतर होता है। नई दरों के अनुसार मुंबई में 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 912.50 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये और चेन्नई में 928.50 रुपये का हो गया है। नोएडा में भी घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली के बराबर 913 रुपये हो गई है।

होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 114.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद नई दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 1,883 रुपये हो गई है। इससे पहले एक मार्च को भी 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 28 रुपये की वृद्धि की गई थी।

नए दामों के अनुसार, मुंबई में 19 किलोग्राम का वाणिज्यिक सिलेंडर 1,835 रुपये में मिलेगा, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत बढ़कर 1,990 रुपये और चेन्नई में 2,043.50 रुपये हो गई है। इस वर्ष अब तक वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कुल 302.50 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत जारी रहेगी। योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने वाले 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को साल में 12 सिलेंडर तक प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती रहेगी।

टी20 विश्व कप के फाइनल में आज होगी भारत-न्यूजीलैंड के बीच जंग

भारतीय टीम 2024 में ट्रॉफी जीत चुकी है, कीवी ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

टीम इंडिया टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार, 8 मार्च को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। साथ ही टॉस आधा घंटे पहले शाम 6:30 बजे होगा। इस बीच क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। इसमें प्यूर्टो के रिको के पॉप स्टार रिकी मार्टिन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे।

दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट में 1-1 मैच गंवाया है। ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका ने कीवी टीम को 7 विकेट से मात दी थी। साथ ही उनका सुपर-8 का पहला मैच बारिश के कारण रद हो गया था। वहीं भारतीय टीम को सुपर-8 के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

अब भारत और न्यूजीलैंड टीम फाइनल में हैं। कीवी टीम ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। ऐसे में उनके पास इतिहास रचने का मौका है। वहीं भारतीय टीम 2024 में ट्रॉफी उठा चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया खिताब का बचाव करने उतरेगी।

भारतीय टीमः ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह।

न्यूजीलैंड टीमः मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवॉन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन, कोल मैककॉन्ची

बारिश से धुला फाइनल, तो क्या होगा

टी20 विश्व कप में 2 मैच बारिश के कारण रद हो चुके हैं। ऐसे में फैंस को टेंशन है कि कहीं बारिश उनकी उम्मीदों पर पानी न फेर दे। साथ ही क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो कौन सी टीम चैंपियन होगी? क्या फाइनल मैच के लिए कोई रिजर्व डे रखा गया है? ***रिजर्व डे रखा गया हैः*** बता दें कि टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच के लिए 9 मार्च रिजर्व डे है। अगर रविवार को मैच नहीं हो पाता है तो इसे सोमवार को पूरा किया जाएगा। मैच का रिजल्ट निकालने के लिए कम से कम 10-10 ओवर का खेल होना जरूरी है। अगर 1 टीम 20 ओवर खेल लेती है और उसके बाद बारिश होती है तो डीएलएस मैथ्ड से रिजल्ट निकालने के लिए दूसरी टीम को कम से कम 10 ओवर खेलने होंगे। अगर रविवार को मैच अधूरा रह जाता है और अतिरिक्त समय में भी पूरा नहीं होता है तो सोमवार को वहीं से शुरू होगा, जहां से 8 मार्च को खत्म हुआ था। दोनों ही दिन मैच पूरा कराने के लिए अतिरिक्त 120-120 मिनट होंगे। अगर मैच डे और रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो पाता है तो अंत में भारत और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से विनर घोषित कर दिया जाएगा। ***पहले भी धुल चुका फाइनलः*** बता दें कि अब तक एक बार ही आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल मैच रद हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। बारिश के कारण यह मैच पूरा नहीं हो पाया था, ऐसे में दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया था।

गाएल मोनफिल्स ने बीएनपी परिबास ओपन से ली भावुक विदाई

- दूसरे दौर में हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर

एजेंसी (हि.स.)
इंडियन वेल्स

फोटोः हि.स.

कैलिफोर्निया में खेले जा रहे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट बीएनपी परिबास ओपन में फ्रांस के दिग्गज खिलाड़ी गाएल मोनफिल्स ने भावुक विदाई ली। दूसरे दौर के मुकाबले में उन्हें कनाडा के फेलिक्स ऑगर-अलियासिम के खिलाफ 6-7(5), 6-3, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही मोनफिल्स का इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। मैच के बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उन्हें खड़े होकर तालियों के साथ सम्मानित किया।

39 वर्षीय मोनफिल्स ने पहले ही संकेत दिया है कि यह उनका आखिरी सीजन हो सकता है। मुकाबले के बाद उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट से जुड़ी यादें उनके लिए बेहद खास हैं। उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए अविश्वसनीय टूर्नामेंट रहा है। मैं थोड़ा भावुक हूं। आमतौर पर मैं उदास नहीं होता, लेकिन आज थोड़ा दुख जरूर महसूस हो रहा है।' मोनफिल्स ने बताया कि बचपन से उनका सपना बड़े टूर्नामेंटों में बड़ी भीड़ के सामने खेलने का था और इंडियन वेल्स ने उनकी सभी उम्मीदों को पूरा किया।

अपने शानदार एथलेटिक अंदाज और मनोरंजक खेल शैली के लिए मशहूर मोनफिल्स ने अपने करियर में कुल 13 एटीपी टूर खिताब जीते। उनका सबसे हालिया खिताब पिछले साल ऑकलैंड में आया था, जो 2005 में पोलैंड में जीते गए उनके पहले खिताब के लगभग 20 साल बाद था। मोनफिल्स ने कहा कि इस साल उन्हें टूर्नामेंट में वाइल्डकार्ड मिलने के लिए वह आयोजकों के आभारी हैं और इंडियन वेल्स हमेशा उनके लिए खुशियों से भरी जगह रहा है। मोनफिल्स का करियर ऐसे दौर में रहा जब पुरुष टेनिस पर तीन महान खिलाड़ियों– रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच –का लगभग दो दशकों तक दबदबा रहा। फिर भी उन्होंने दो ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल खेले–2008 में फ्रेंच ओपन और 2016 में यूएस ओपन।

मोनफिल्स ने कहा कि वह अपने करियर से पूरी तरह संतुष्ट हैं और टेनिस से विदा लेते समय उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं है।

अबूधाबी के बजाय दक्षिण अफ्रीका में अभ्यास करेगी इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम

एजेंसी (हि.स.)
लंदन

फोटोः हि.स.

इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते आगामी श्रृंखलाओं की तैयारी के लिए अबूधाबी के बजाय दक्षिण अफ्रीका में अभ्यास शिविर में भाग लेगी। इंग्लैंड की 30 सदस्यीय टीम प्रिटोरिया में अभ्यास शिविर में हिस्सा लेगी जहां वह 10 से 27 मार्च के बीच आपस में ही पांच मैच खेलेगी। इसके लिए 15-15 खिलाड़ियों की दो टीम तैयार की गई हैं।

टीमों के नाम इंग्लैंड की दो महान खिलाड़ियों जेन ब्रिटिन और राचेल हेहो फ्लिंट के नाम पर रखे गये हैं। यह दोनों घरेलू धरती पर विश्व कप जीतने वाली टीमों की सदस्य थीं। इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट टीम ब्रिटिन की कप्तानी करेंगी, जिसके कोच डरहम के पूर्व बल्लेबाज और इंग्लैंड की महिला टीम के सहायक कोच जॉन लुईस होंगे। उपकप्तान चार्ली डीन टीम हेहो फ्लिंट की कप्तानी करेंगी। यह टीम सहायक कोच ल्यूक विलियम्स टीम के मार्गदर्शन में खेलेगी। मुख्य कोच शार्लोट एडवर्ड्स शिविर के दौरान दोनों टीमों पर निगरानी रखेंगी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा है कि आगामी टी20 विश्व कप को देखते हुए उन्हें इस श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी दावेदारी मजबूत करनी होगी। एडवर्ड्स ने विज्ञप्ति में कहा, शिविर में शामिल प्रत्येक खिलाड़ी के लिए यह बड़ा अवसर है कि वे अपनी काबिलियत साबित करके यह दिखाएं कि वे हमारी विश्व कप योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह इस साल दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड का दूसरा अभ्यास शिविर होगा।

अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टर रुस्तम सारंग को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में सहायक संचालक के पद की जिम्मेदारी

एजेंसी (हि.स.)
रायपुर

फोटोः हि.स.

छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टर रुस्तम सारंग को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति देते हुए सहायक संचालक के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुस्तम सारंग ने 13 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। सारंग ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन और उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया।

रुस्तम सारंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। खेल के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और उपलब्धियों को देखते हुए राज्य शासन ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ महीनों से अन्य दायित्वों के चलते वे खेल प्रशिक्षण और गतिविधियों से दूर थे, जिससे कई छोटे खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब नई जिम्मेदारी के साथ वे फिर से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उन्हें यह दायित्व फरवरी के अंतिम सप्ताह में सौंपा गया है।

छत्तीसगढ़ के अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टर रुस्तम सारंग ने वर्ष 2005 में जूनियर एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और छत्तीसगढ़ के पहले अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी बने। इसके बाद 2006 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य और 2007 गुवाहाटी नेशनल गेम्स में रजत पदक हासिल किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 2009 मलेशिया, 2011 दक्षिण अफ्रीका और 2012 समोआ में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। वहीं पेरिस (2011) और कजाखस्तान (2014) वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप तथा 2015 केरल नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के शहीद कौशल यादव खेल पुरस्कार, शहीद राजीव पांडेय खेल पुरस्कार और गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।

रुस्तम सारंग छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी के पद पर पदस्थ रहे और एसएआई (साई) पटियाला से स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा प्राप्त कर कई युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दिया। हाल ही में उन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की थी।

ऑल इंग्लैंड ओपन 2026: लक्ष्य सेन ने ली शी फेंग को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

एजेंसी (हि.स.)
बर्मिंघम

फोटोः हि.स.

भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल क्वार्टरफाइनल में चीन के ली शी फेंग को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 24 वर्षीय लक्ष्य सेन ने शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में शुरूआत से ही दबदबा बनाए रखा और ली शी फेंग को सीधे गेमों में 21-13, 21-16 से हराया। यह मैच 45 मिनट तक चला, जिसमें भारतीय खिलाड़ी ने आक्रामक और सटीक खेल का प्रदर्शन किया।

पहले गेम में लक्ष्य सेन पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने शुरूआत में बढ़त बना ली और लगातार छह अंक हासिल करते हुए आसानी से गेम अपने नाम कर लिया। दूसरा गेम अपेक्षाकृत कड़ा रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ियों के बीच कई बार बढ़त बदलती रही। हालांकि, निर्णायक क्षणों में लक्ष्य सेन ने लगातार अंक जुटाकर बढ़त को मजबूत किया और अंततः मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना कनाडा के विक्टर लाई और जापान के कोटा वतनाबे के बीच होने वाले क्वार्टरफाइनल मैच के विजेता से होगा। यह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन का तीसरा सेमीफाइनल होगा।

दर्पण विशेष

महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

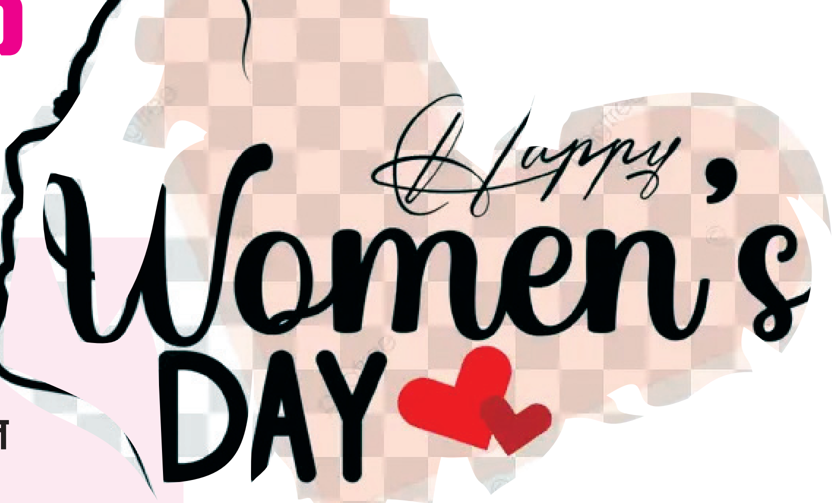

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपने अधिकारों की लड़ाई में महिलाओं की उपलब्धियों और वे कितनी दूर तक पहुंची हैं, इसका जश्न मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने वाला एक वैश्विक दिवस है। यह दिन दुनिया भर में लैंगिक असमानता के खिलाफ कार्रवाई करने के समर्थन में भी मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया महिलाओं के बिना नहीं चल सकती। यह उनके प्रयासों की सराहना करने का दिन है।

महिला दिवस की शुरूआत और इतिहास

इसकी शुरूआत 1975 में हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने 'इंटरनेशनल विमेंस ईयर' मनाते हुए पहली बार इंटरनेशनल विमेंस डे का आयोजन किया था। इसके दो साल बाद यानी साल 1977 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 8 मार्च को 'महिला अधिकार दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की। हालांकि, महिला दिवस का इतिहास इससे कहीं पहले का है। 28 फरवरी, 1909 को अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने इसे पहली बार मनाया था। इसके बाद महिला दिवस को लेकर संघर्ष और आंदोलनों की एक लंबी प्रक्रिया चली, जिसमें महिलाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई।

महिला दिवस का महत्व

महिला दिवस का उद्देश्य महिलाओं के संघर्ष, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना है। यह दिन समाज को यह याद दिलाने का अवसर है कि महिलाओं को अब भी पुरुषों के निर्णयों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वह घर हो या वर्किंग प्लेस। इस दिन के जरिए महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर मिलने की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है।

महिला दिवस 2026 की थीम

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की वैश्विक थीम है, 'दान से लाभ' यानी जब आप किसी को कुछ देते हैं तो बदले में आपको भी लाभ होता है।

8 मार्च का चुनाव क्यों

इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए 8 मार्च की तारीख का चुनाव एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। 1917 में रूस में महिलाओं ने एक ऐतिहासिक हड़ताल की थी, जो पॉलिटिकल बदलाव का कारण बनी। उस समय रूस में जुलियन कैलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, जबकि बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर था। जुलियन कैलेंडर के अनुसार 1917 का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में वही तारीख 8 मार्च को थी। इसके बाद 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई।

महिलाओं के अधिकारों पर प्रगति

89 प्रतिशत सरकारों के लिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करना एक सर्वोच्च प्राथमिकता है, और 193 देशों ने इसके खिलाफ कानूनी उपाय किए हैं। डेटा से स्पष्ट होता है कि जिन देशों में घरेलू हिंसा कानून हैं, वहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में कमी आई है। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता लगभग हासिल कर ली गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर और लैंगिक अंतर को समाप्त करके, हम समान अवसरों के लिए बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कई देशों ने देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाया है और वैश्विक स्तर पर 32 प्रतिशत देश अब देखभाल करने वालों के लिए बेहतर वेतन और सुरक्षित कार्य स्थितियों को बढ़ावा दे रहे हैं। शांति और सुरक्षा प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल करने के लिए 112 देशों ने राष्ट्रीय योजनाएं बनाई हैं - 2010 में केवल 19 देशों की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

भारत में महिला सशक्तिकरण: एक सशक्त भविष्य की ओर

भारत में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसके लिए सरकार सक्रिय रूप से विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कानूनों के माध्यम से प्रयास कर रही है। देश अब महिला विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर अग्रसर है, जो राष्ट्रीय प्रगति में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। आज, महिलाएं भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशन और नेतृत्व के क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। **सरकार की पहलें:** भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं लागू की गई हैं, जो उन्हें हिंसा और शोषण से बचाने में मदद करती हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने और उन्हें प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। 3 मार्च, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले नमो ऐप ओपन फोरम पर भारत भर की महिलाओं को अपनी प्रेरणादायक जीवन यात्रा साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सख्त कानून और रस्म अदायगी के बीच दम तोड़ती महिला सुरक्षा

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक समानता में तेजी लाने के लिए कार्रवाई के आ'ान का भी प्रतीक है। हालांकि चिंता का विषय यही है कि जिस 'आधी दुनिया' के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, उसी आधी दुनिया को जीवन के हर मोड़ पर भेदभाव या अपराधों का सामना करना पड़ता है। यदि इसे भारत के ही संदर्भ में देखें तो शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो, जब 'आधी दुनिया' से जुड़े अपराधों के मामले देश के कोने-कोने से सामने न आते हों। होता सिर्फ यही है कि जब भी कोई बड़ा मामला सामने आता है तो हम सिर्फ पुलिस-प्रशासन को कोसने और संसद से लेकर सड़क तक कैंडल मार्च निकालने या अन्य किसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन करने की रस्म अदायगी करके शांत हो जाते हैं और पुनः तभी जागते हैं, जब ऐसा ही कोई बड़ा मामला पुनः सुर्खियां बनता है, अन्यथा ऐसी छोटी-मोटी घटनाएं तो आए दिन होती ही रहती हैं। देश में कानूनों में सख्ती, महिला सुरक्षा के नाम पर बीते कुछ वर्षों में कई तरह के कदम उठाने और समाज में 'आधी दुनिया' के आत्मसम्मान को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि बलात्कार के मामले हों या छेड़छाड़ अथवा मयार्दा हनन या फिर अपहरण अथवा क्रूरता, 'आधी दुनिया' के प्रति अपराधों का सिलसिला थम नहीं रहा है? इसका एक बड़ा कारण तो यही है कि कड़े कानूनों के बावजूद असामाजिक तत्वों पर वो कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके वो हकदार हैं और इसके अभाव में हम ऐसे अपराधियों के मन में भय पैदा करने में असफल हो रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि महज कानून कड़े कर देने से ही महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध थमने से रहे, जब तक उनका ईमानदारीपूर्वक कड़ाई से पालन न किया जाए। ऐसे मामलों में पुलिस-प्रशासन की भूमिका भी अनेक अवसरों पर संदिग्ध रहती है। पुलिस किस प्रकार ऐसे अनेक मामलों में पीड़िताओं को ही परेशान करके उनके जले पर नमक छिड़कने का कार्य करती है, ऐसे उदाहरण अक्सर सामने आते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का भय कैसे उत्पन्न होगा और कैसे महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी की उम्मीद की जाए? जरूरत इस बात की महसूस की जाने लगी है कि पुलिस को लैंगिक दृष्टि से संवदेनशील बनाया जाए ताकि पुलिस पीड़ित पक्ष को पर्याप्त संबल प्रदान करे और पीड़िताएं अपराधियों के खिलाफ खुलकर खड़ा होने की हिम्मत जुटा सकें, साथ ही जांच एजेंसियों और न्यायिक तंत्र से भी ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई की अपेक्षा की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए समय की मांग यही है कि सरकारें मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त बनाने के साथ-साथ प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करें कि यदि उनके क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के मामलों में कानून का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। दिनदहाड़े सामने आती छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं सभ्य समाज के माथे पर बदनुमा दाग के समान हैं और यह कहना असंगत नहीं होगा कि महज कड़े कानून बना देने से ही महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगने वाला। आए दिन देशभर में हो रही इस तरह की घटनाएं हमारी सभ्यता की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बलात्कार और छेड़छाड़ के आए दिन जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे भी होते हैं, जिनमें पीड़िता के परिजन, निकट संबंधी या परिचित ही आरोपी होते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों में तो यहां तक कहा जा चुका है कि करीब 97 फीसदी मामलों में महिलाएं अपनों की ही शिकार होती हैं और यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि महिला अपराधों के मामले में पूरी दुनिया की यही तस्वीर है। जहां देश में हर 53 मिनट में एक महिला यौन शोषण की शिकार होती है और हर 28 मिनट में अपहरण का मामला सामने आता है, वहीं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में प्रत्येक तीन में से एक महिला का कभी न कभी शारीरिक शोषण होता है। दुनिया में करीब 71 फीसदी महिलाएं शारीरिक मानसिक प्रताड़ना अथवा यौन शोषण व हिंसा की शिकार होती हैं, दक्षिण अफ्रीका में हर छह घंटे में एक महिला को उसके साथी द्वारा ही मौत के घाट उतार दिया जाता है और अमेरिका में भी इसी प्रकार कई महिलाएं हर साल अपने ही परिचितों द्वारा मार दी जाती हैं। जहां तक पीड़िताओं को न्याय दिलाने की बात है तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग काफी समय से उठती रही है किन्तु हमारा सिस्टम कछुआ चाल से रेंग रहा है। ऐसे मामलों में कठोरता बरतने के साथ-साथ त्वरित न्याय प्रणाली की भी सख्त जरूरत है ताकि महिला अपराधों पर अंकुश लग सके। आज अगर समाज में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध और संवेदनहीनता के मामले बढ़ रहे हैं तो हमें यह जानने के प्रयास करने होंगे कि कमी हमारी शिक्षा प्रणाली में है या कारण कुछ और हैं। ऐसे कृत्यों में लिप्त रहने वाले लोगों की कुंठित मानसिकता के कारणों की पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है, साथ ही सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को लागू करना और छात्रों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना समय की मांग है ताकि युवाओं की नकारात्मक सोच को परिवर्तित करने में मदद मिल सके, जिससे स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सके।

पीजीआई ने 12वां सालाना रिसर्च डे मनाया, लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन पर रहा फोकस

रिसर्च एक लंबा सफर है जो सब्र, जुनून और लगन पर बना है: प्रो. निखिल टंडन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पिछले एक साल में पब्लिश हुए 329 रिसर्च पेपर दिखाए गए, सर्जिकल, मेडिकल और बेसिक साइंस फील्ड में रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 35 रिसर्चर को अवॉर्ड मिले और 59 रिसर्चर को उनके शानदार और भरोसेमंद रिसर्च काम के लिए इनोवेशन कैटेगरी में अवॉर्ड मिला, पीजीआई का 12वां सालाना रिसर्च डे, जो मेडिकल रिसर्च का बड़ा शोकेस है, आज यहां पीजीआई में एक अच्छे नोट पर खत्म हुआ। चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, प्रो. निखिल टंडन, डीन, एम्स नई दिल्ली, ने पीजीआई में हो रही रिसर्च की गहराई, विविधता और क्वालिटी की तारीफ करते हुए कहा, पीजीआई में हो रही रिसर्च के दायरे और विस्तार को देखने के बाद, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ हो रहे काम की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। इस संस्थान में साइंटिफिक कम्युनिटी साफ तौर पर समझती है कि मेडिकल ज्ञान को आगे बढ़ाने और मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है।

प्रो. टंडन ने डॉक्टर की दुविधा नाम से एक खास भाषण दिया, जहाँ उन्होंने डॉक्टर-साइंटिस्टों के सामने आने वाली मुश्किल ज़िम्मेदारियों पर बात की। भारत में ज्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल दो टोपियाँ पहनते हैं—एक मरीजों की देखभाल करना और दूसरी रिसर्च करना। इन ज़िम्मेदारियों में बैलेंस बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम हेल्थकेयर को बेहतर बनाना चाहते हैं और काम का साइंटिफिक ज्ञान पैदा करना चाहते हैं तो यह जरूरी है। रिसर्च कभी भी छोटा सफर नहीं होता। इसका असली असर दिखने से पहले इसमें सब्र की जरूरत होती है—कभी-कभी सालों या दशकों तक भी। आज हम जो काम करते हैं, हो सकता है कि वह हेल्थकेयर को तुरंत न बदले, लेकिन कमिटमेंट और मेहनत से यह आखिरकार समाज को फायदा पहुंचाने वाले ज्ञान में योगदान देता है, जैसा कि प्रो. टंडन ने साइंटिफिक खोज के नेचर के बारे में कहा, और इस बात पर जोर दिया कि असरदार रिसर्च के लिए सब्र और लगातार कोशिश की जरूरत होती है। चीफ गेस्ट ने मेंटरशिप और मिलकर काम करने वाले एकेडमिक माहौल के महत्व पर भी जोर दिया, उन्होंने कहा, महान रिसर्च शायद ही कभी अकेले होती है। जो इंस्टीट्यूशन मेंटरशिप, मिलकर काम करने और रिसर्च करने वालों की एक बड़ी संख्या को बढ़ावा देते हैं, वे ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ आइडिया पनपते हैं और इनोवेशन मुमकिन होता है। इससे पहले, प्रो. विवेक लाल, डायरेक्टर, पीजीआई ने चीफ गेस्ट का स्वागत करते हुए, इंस्टीट्यूट के साइंटिफिक जांच और रिसर्च एक्सीलेंस के मजबूत कल्चर पर रोशनी डालते हुए कहा, इंस्टीट्यूट पर बहुत ज्यादा क्लिनिकल वर्कलोड होने के बावजूद, जब पेशेंट केयर की बात आती है तो पीजीआई बहुत ऊंचे पायदान पर है। सालाना लगभग 40 लाख पेशेंट के आने के साथ, हमारे डॉक्टर हेल्थकेयर सर्विस देने में पूरी तरह से लगे रहते हैं। फिर भी, इस बहुत ज्यादा प्रेशर के बावजूद, हमारी फैकल्टी, रेजिडेंट और हेल्थकेयर प्रोफेशनल बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ हाई-क्वालिटी रिसर्च करते रहते हैं। पीजीआई में सालाना रिसर्च डे को रिसर्च की दिवाली बताते हुए, प्रो. लाल ने कहा, रिसर्च डे वह समय होता है जब इंस्टीट्यूट की पूरी साइंटिफिक कोशिशें एक साथ आती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि पेशेंट केयर की बहुत ज्यादा मांगों के अलावा, हमारी फैकल्टी और रेजिडेंट के बीच नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाने का भी उतना ही मजबूत कमिटमेंट है।

इंस्टीट्यूशन की रिसर्च अचीवमेंट्स पर रोशनी डालते हुए, प्रो. संजय जैन, डीन (रिसर्च), पीजीआई ने एनुअल रिसर्च ओवरव्यू पेश करते हुए कहा, अकेले पिछले साल में, हमारे इंस्टीट्यूशन ने ICMR, DBT, DST और CSIR जैसी एजेंसियों के जरिए 250 एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे लगभग 140 करोड़ की ग्रांट मिली। ये नंबर सिर्फ. स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं—ये उन सैकड़ों सवालों को दिखाते हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा रहा है और पेशेंट केयर को बेहतर बनाने के लिए सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं।

नारी शक्ति, ममता, और त्याग का स्वरूप: बन्तो कटारिया

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष बन्तो कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता दी जाती है। बन्तो कटारिया ने कहा नारी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वह जीवनदायिनी है, प्रेम की मूर्ति और रिश्ते संवारने वाली शक्ति है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, ममता, और त्याग का स्वरूप माना गया है। बन्तो कटारिया ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के हितार्थ चलाई जाने वाली योजनाओं चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश व देश की महिलाएं सशक्त हो, उनके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लखपति दीदी जैसी योजनाओं पर धरातल पर लाया गया। महिलाओं को सशक्त करने एवं उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए संसद में एक तिहाई आरक्षण देकर महिलाओं की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना है।

बन्तो कटारिया ने कहा इस वर्ष का यह विषय सभी के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसर प्रदान करने तथा एक समावेशी भविष्य के लिए कार्य करने का आान करता है जहां कोई भी पीछे न छूटे। इस दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य अगली पीढ़ी यानि युवाओं, विशेष रूप से युवा महिलाओं और किशोरियों को स्थायी परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में सशक्त बनाना है। बन्तो कटारिया ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ० हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में केंद्र ० राज्य सरकार विभिन्न नीतियों, योजनाओं और विधायी उपायों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। देश महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जो राष्ट्रीय प्रगति में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।

पंजाब के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने की दिशा में पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय का बड़ा कदम

सिटी दर्पण संवाददाता
बठिंडा

युवाओं में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू पंजाब), बठिंडा ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप छह नए कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह पहल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल से सुसज्जित करना और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित ह्लआत्मनिर्भर भारतह्व और ह्लविकसित भारतह्व के राष्ट्रीय विजन को साकार करने में योगदान देना है। इससे पहले विश्वविद्यालय को एनसीवीईटी द्वारा ह्लडीम्ड अवार्डिंग बॉडी -ड्यूल स्टेटस प्रदान किया गया था, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने, मूल्यांकन करने और सफल अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत है। विश्वविद्यालय ने परिसर में छह नए कौशल विकास पाठ्यक्रमों की शुरूआत की घोषणा की है, जिनकी कक्षाएं अप्रैल 2026 से आरंभ होंगी। इन पाठ्यक्रमों में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स (120 घंटे), इंट्रोडक्शन टू टैली ऑपरेशंस एंड जीएसटी कैलकुलेशंस (120 घंटे), बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ (30 घंटे), असिस्टेंट कारपेंटर (40 घंटे), हेल्पर इलेक्ट्रीशियन (270 घंटे) तथा एसेंशियल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग (15 घंटे) शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों की शुरूआत विश्वविद्यालय की कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कुलसचिव डॉ. विजय शर्मा ने बताया कि ये पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं।

संक्षिप्त-समाचार

डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, पंचकूला ने जिला के तीन शेल्टर होम्स का किया औचक निरीक्षण

पंचकूला। श्री अजय कुमार घनघस, सीजेएम -कम-सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएलएसए), डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पंचकूला ने बताया कि आज श्री संजय संधीर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, पंचकूला ने जिला के तीन शेल्टर होम्स, बाल निकेतन, सेक्टर-2 पंचकूला, शिशु गृह, सेक्टर-15 पंचकूला और आशियाना, सेक्टर-16 पंचकूला का औचक निरीक्षण किया। यह विज़िट इन इंस्टीट्यूशन्स में रहने वाले बच्चों के रहने के हालात और उन्हें दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए की गई थी। श्री अजय कुमार घनघस विज़िट के दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के साथ थे। यह इंस्पेक्शन यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि इन शेल्टर होम्स में रहने वाले बच्चों को सही देखभाल, सुरक्षा और वेलफेयर के उपाय दिए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान, श्री संजय संधीर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने रहने वालों से बातचीत की और उनकी भलाई, डेली रूटीन, पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज के बारे में पूछा। उन्होंने शेल्टर होम के कामकाज और बच्चों के लिए मौजूद सुविधाओं के बारे में इंस्टीट्यूशन के स्टाफ मेंबर और मैनेजमेंट से भी बात की। डिस्ट्रिक्ट जज ने बच्चों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया। इसके अलावा, उन्होंने शेल्टर होम में रहने वाले बच्चों और उनकी रोजाना की एक्टिविटी के बारे में रखे गए रिकॉर्ड को रिव्यू किया। अजय कुमार घनघस ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, पंचकूला बच्चों के अधिकारों और भलाई की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऐसे इंस्टीट्यूशन के काम करने के तरीके पर नजर रखना जारी रखेगी ताकि यह पक्का हो सके कि बच्चों को सही देखभाल, सुरक्षा और उनके पूरे विकास के लिए अच्छा माहौल मिले।

SAI NSNIS पटियाला में शुरू; MP डॉ. धर्मवीर गांधी ने इवेंट का उद्घाटन किया

पटियाला। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के जरिए FIT इंडिया मूवमेंट के तहत ठरठक्र कैंपस में 7 मार्च से 9 मार्च, 2026 तक FIT इंडिया कार्निवल 2026 शुरू किया है। इसका मकसद फिटनेस मजेदार है का मैसेज देना और लोगों को हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए बढ़ावा देना है। कार्निवल का उद्घाटन आज पटियाला के माननीय टढ डॉ. धर्मवीर गांधी ने SAI NSNIS पटियाला में हुई ओपनिंग सेरेमनी में विनीत कुमार DDG/Sr. ED और दूसरे लोगों की मौजूदगी में किया। अपने भाषण में, डॉ. गांधी ने रोजमर्रा की ज़िंदगी में फिटनेस की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि खेल के मैदान ही असली प्लैटफॉर्म हैं जहाँ जाति, धर्म या जगह से ऊपर उठकर टैलेंट निखरता है, और बराबरी और काबिलियत को बढ़ावा मिलता है। पहले दिन NCOE एथलीट, NSNIS डिप्लोमा ट्रेनी, कोच, स्टाफ मेंबर और फिटनेस के शौकीन लोगों समेत 1000 से ज्यादा लोगों ने एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, जिससे यह हेल्थ और कम्युनिटी की भागीदारी का एक शानदार सेलिब्रेशन बन गया।

यूपीएससी में तीसरी रैंक पाने वाले एकांश ढुल को कुलभूषण गोयल ने दी बधाई

पंचकूला। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले एकांश ढुल को शनिवार को पंचकूला के पूर्व महापौर कुलभूषण गोयल ने उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पूर्व पार्षद जय कौशिक और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सुखबीर पूनिया भी उनके साथ मौजूद रहे। सभी ने एकांश ढुल को उनकी इस बड़ी उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं। कुलभूषण गोयल ने कहा कि यह पंचकूला के लिए बेहद गर्व की बात है कि शहर के एक युवा ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में तीसरा स्थान हासिल कर प्रदेश और शहर का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि एकांश ने लगातार तीन बार यूपीएससी परीक्षा पास कर यह साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे एकांश ढुल से प्रेरणा लें और जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर पूरी लगन और मेहनत के साथ उसे हासिल करने का प्रयास करें।